राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 272 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, शनिवार, 03 अप्रैल 2021, मूल्य रु. 1.50

ईवीएम मामले में 4 अधिकारी निलंबित

गुवाहाटी, (एजेंसी)। पूर्वोत्तर राज्य असम में ईवीएम मामले में चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के चार अधिकारियों को असम ईवीएम मामले में निलंबित कर दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि परिवहन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए पीठासीन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही पीओ और तीन अन्य अधिकारियों को निलंबित किया गया है। हालांकि, ईवीएम की सील बंद मिली, लेकिन एलएसी 1 रतबाड़ी(एससी) के इंदिरा एमवी स्कूल, संख्या 149 पर दोबारा मतदान कराने का फैसला किया गया है।

चुनाव आयोग ने असम में ईवीएम से जुड़ी घटना पर तथ्यात्मक रिपोर्ट जारी की है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि पोलिंग पार्टी 149-इंदिरा एमवी स्कूल ऑफ एलएसी 1 रतबारी (एससी) का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। उस पोलिंग पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी और 3 मतदान कर्मी शामिल थे। उनके साथ एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड शामिल पुलिस कर्मी भी थे।

इससे पहले असम में भाजपा उम्मीदवार की कार में ईवीएम मिलने के मामले में चुनाव आयोग ने जांच शुरू की। चुनाव आयोग को भाजपा विधायक की गाड़ी में ईवीएम मिले जाने की अब तक जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक असम में पोलिंग पार्टी की गाड़ी खराब हो गई थी जिसके बाद पीठासीन अधिकारी ने भाजपा विधायक की गाड़ी में लिफ्ट लेने की बात कही है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, लिफ्ट लेकर जब भाजपा विधायक की गाड़ी से पोलिंग पार्टी लौट रही थी तभी स्थानीय लोगों ने देख लिया और गाड़ी रोक दिया। पोलिंग पार्टी के सदस्यों को स्थानीय लोगों ने गाड़ी से निकाल दिया और भीड़ हिंसात्मक भी होने लगी।

चुनाव आयोग को मिली सूचना के मुताबिक जो ईवीएम बीजेपी विधायक की गाड़ी से मिला है वोटिंग के बाद की है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक ईवीएम का सील नहीं टूटा है। इस बीच चुनाव आयोग को जिला निर्वाचन अधिकारी से दूसरी रिपोर्ट का भी चुनाव है को इंतजार है।

असम विधानसभा चुनाव 2021 की पथरकंडी सीट पर दूसरे चरण में कल 1 अप्रैल को वोटिंग हुई। इस वोटिंग के बाद असम में ईवीएम मामला सामने आया। वोटिंग के बाद पथराखंडी से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदू पॉल मुश्किलों में फंस गए। कांग्रेस ने उनकी कार से ईवीएम मिलने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से इस मामले पर जवाब मांगा। बताया गया कि ये ईवीएम वोटिंग के बाद बीजेपी उम्मीदवार की कार में मिली है। कांग्रेस नेता सरल पटेल ने एक ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी थी और कहा कि कृष्णेंदू पॉल के कार से ईवीएम पाई गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि ईवीएम उनकी कार में क्यों और कैसे हैं। इस मामले की जांच होनी चाहिए। असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में गुरुवार को 77.21 प्रतिशत मतदान हुआ। दूसरे चरण के चुनाव में 13 जिलों में 10,592 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

हमारी सरकार सेवा करने से पहले लोगों का धर्म नहीं देखती : मोदी

कन्याकुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह ऐसी अहंकारी पार्टी है जो स्थानीय संवेदनाओं को नहीं समझती। प्रधानमंत्री ने साथ ही यह भी दावा किया कि उनकी सरकार लोगों की सेवा करने के मामले में जाति या धर्म नहीं देखती है। मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में चुनावी रैली में कहा कि द्रमुक में हालात ऐसे थे कि पार्टी के सरंक्षक दिवंगत एम करुणानिधि के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने वाले वरिष्ठ नेता पार्टी के नए शहजादे (द्रमुक युवा शाखा के सचिव उदयनिधि स्टालिन) के चलते घुटन महसूस कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, राजनीति इस तरह नहीं होती। आज देश का मिजाज स्पष्ट तौर पर भाई-भतीजावाद और अधिकारवाद की राजनीति के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष लोगों को लोकतंत्र-विरोधी कहना पसंद करता है लेकिन उन्हें स्वयं आईना देखना चाहिए। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कई बार अनुच्छेद 356 लगाया है। द्रमुक और अन्नाद्रमुक, दोनों ही सरकारों को पूर्व में कांग्रेस द्वारा बर्खास्त किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी भी गठबंधन में कांग्रेस का होना एक ऐसे अहंकारी सहयोगी की तरह है, जो स्थानीय संवेदनाओं को नहीं समझता है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी विचारधारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है और इस मंत्र के मूल में सभी के प्रति करुणा की भावना है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार लोगों की सेवा करने से पहले उनकी जाति, पंथ या धर्म नहीं देखती है। हमारी सरकार सभी के लिए है। कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर उप चुनाव छह अप्रैल को होना हैं।

गुड फ्राइडे के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में बाइबल का हवाला देते हुए सत्तारूढ़ माकपा नीत एलडीएफ और कांग्रेस नीत यूडीएफ को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दोनों मोर्चा ने सत्ता के लिए लालच एवं लिप्सा सहित सात घातक पाप किए हैं। मोदी ने शुक्रवार को यहां एक चुनावी रैली में दोनों मोर्चा पर प्रहार करते हुए कहा, आप सभी ने सात घातक पाप के बारे में सुना होगा। यूडीएफ और एलडीएफ ने केरल में सात घातक पाप किए हैं। दोनों मोर्चा ने बारी-बारी से राज्य में कई वर्षों तक शासन किया है। उन्होंने सोना, डॉलर और सौर मामलों का हवाला देते हुए कहा, पहला पाप है घमंड। यूडीएफ और एलडीएफ को लगता है कि उन्हें कभी हराया नहीं जा सकता है। इससे उनके नेता काफी घमंडी हो गए हैं और अपनी जड़ों से कट गए हैं, जबकि उनका दूसरा पाप धन की लालच है। इन मामलों से दोनों मोर्चा की छवि खराब हुई है। मोदी ने दावा किया कि दोनों मोर्चा ईर्ष्यालु हैं और गलत काम करने के लिए उनके बीच होड़ मची हुई है। प्रधानमंत्री ने यहां एक स्टेडियम में आयोजित रैली में कहा, उनके बीच भ्रष्टाचार की प्रतियोगिता है। अगर एक मोर्चा दूसरे से ज्यादा पैसा बनाता है तो उन्हें ईर्ष्या होती है। उन्होंने आरोपलगाया कि सत्ता की लालच के कारण दोनों मोर्चा ने समाज के सांप्रदायिक, आपराधिक और दमनकारी तत्वों के साथ गठबंधन किया है। उन्होंने कहा, तीन तलाक पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का रूख क्या था? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की सामाजिकनीतियां क्या हैं? क्या उनकी पीछे की ओर धकेलने वाली राजनीतिका समर्थन किया जा सकता है? नहीं। मोदी ने कहा कि दोनों मोर्चा वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रहेहैं और बाकी मुद्दे गौण हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को द्रमुक और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके नेता महिलाओं का अपमान करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने रेखांकित किया कि राजग की योजनाओं का लक्ष्य महिलाओं का सशक्तिकरण है। यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने लोगों से छह अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में सहयोगी पार्टी अन्नाद्रमुक समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिवगंत मुख्यमंत्री एम जी रामचंद्रन का, समावेशी विकास एवं समृद्ध समाज का दृष्टिकोण हमें प्रेरित करता है। द्रमुक और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि उनके पास बोलने के लिए कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि साथ चुनाव लड़ रहीं दोनो पार्टियां लोगों की सुरक्षा और मान-सम्मान तक की गारंटी नहीं देंगी और उनके शासन में कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी।

कोरोना के ये चौथी लहर है : केजरीवाल

नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के लिए कोरोना की ये दूसरी वेव हो सकती है लेकिन दिल्ली के लिए ये चौथी वेव (लहर) है।

उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय राजधानी में 3594 केस आए हैं। 16 मार्च को लगभग 425 केस थे। उन्होंने कहा कि कोरोना के केस तेजी से केस बढ़ रहे हैं। ये चिंता की बात है। सरकार की नजर बनी हुई है। जो भी उचित कदम उठाने की जरूरत है वो हम उठा रहे हैं। लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है। भविष्य में अगर जरूरत हुई तो बातचीत के बाद ही फैसला लिया जाएगा।

सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि ये वेव पिछली वेव से कम खतरनाक है। कोरोना से होने वाली मौतें घटी है। उन्होंने कहा कि टेस्ट, ट्रेसिंग और आइसोलेशन का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। आम लोगों की भागीदारी जरूरी है। अनुरोध है कि सभी मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें।

उन्होंने कहा कि आज मीटिंग में हमने अस्पतालों में एम्बुलेंस की व्यवस्था, क्व्व की व्यवस्था, बेड्स की व्यवस्था को लेकर पूरी प्लानिंग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली 3 वेव को दिल्लीवालों ने खूबसूरती से हैंडल किया है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट और टीकाकरण पर सरकार ध्यान दे रही है। बता दें कि गुरुवार को 2790 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे और 9 मरीजों की मौत हुई थी। इससे एक दिन पहले बुधवार को 1,819 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे और 11 लोगों की मौत हुई थी।

टिकैत पर राजस्थान के अलवर में हमला, दिखाए काले झंडे

नई दिल्ली/गाजियाबाद। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता इन दिनों कृषि कानून के विरोध में देश भर में घूम-घूमकर पंचायत व सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। शुक्रवार को वह राजस्थान के अलवर जिले में उनका दो पंचायतों को संबोधित करने का कार्यक्रम था। दोपहर में वह एक पंचायत को संबोधित करने के बाद कुछ गाड़ियों के काफिले के साथ वो दूसरी पंचायत को संबोधित करने के लिए निकले थे। इसी दौरान उन पर हमला हुआ।

भाकियू युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत के अनुसार रास्ते में उन्हें एक राजनीतिक दल के कार्यकताओं ने काले झंड़े दिखाकर विरोध जताया और उन पर पथराव कर दिया। इसमें उनकी गाड़ी के शीशे भी टूट गए। इस हमले में काफिले में मौजूद लोगों का कहना है कि हमलावरों ने गोली भी चलाई। मगर इसकी कोई अधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।

हालांकि वह सुरक्षित बचकर दूसरी पंचायत को संबोधित करने के लिए पहुंच गए।उन्होंने बताया कि चौधरी राकेश टिकैत पर हमले के विरोध और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किसान वहां धरने पर बैठ गए हैं। मौके पर पुलिस को भी बुलाया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और मौके पर मौजूद लोगों से इस बारे में और भी जानकारी हासिल कर रही है जिससे इस तरह की घटना करने वालों की पहचान हो सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके।

बंगाल चुनाव हार चुकी हैं ममता बनर्जी : अमित शाह

बरुईपुर (पश्चिम बंगाल)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्पष्ट रूप से पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग हार चुकी हैं और राज्य में सत्ता में आने वाली नई भाजपा सरकार की पहली बैठक के एजेंडे में संशोधित नागरिकता कानून का मुद्दा उठाया जाएगा। शाह ने आज दिन में दो रोड शो किये जिनमें से एक दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर में और दूसरा हुगली जिले में आरामबाग में था। भाजपा के शीर्ष नेता ने दावा किया कि उन्हें जो फीडबैक प्राप्त हुआ है, उसके मुताबिक पार्टी ने पहले ही उन 60 में से 50 सीटें जीत ली हैं जिन पर पहले दो चरणों में मतदान हुआ था और कुल 294 सीटों वाली विधानसभा में वह 200 से ज्यादा सीट जीतेगी।

बरुईपुर में अपने रोड शो के दौरान उन्होंने एक टीवी चैनल को बताया, हम कुल मिलाकर 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून का मामला पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने वाली भाजपा सरकार की पहली बैठक के एजेंडे में लिया जाएगा। पार्टी राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। ममता बनर्जी के नंदीग्राम चुनाव खासे अंतर से जीतने के दावे के बारे में पूछने पर शाह ने कहा, यह साफ है कि वह चुनाव हार चुकी हैं। वह अब ऐसे बड़े दावे कर रही हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है।

नंदीग्राम सीट पर बनर्जी का मुकाबला कभी उनके सिपहसालार रहे शुभेंदु अधिकारी से है जो इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर दूसरे चरण में एक अप्रैल को मतदान हुआ था। गर्मी के बावजूद सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों का फूलों से सजे ट्रक पर मौजूद शाह ने अभिवादन किया और इस दौरान बड़ी संख्या में हाथों में पार्टी के झंडे लिये कार्यकर्ता जय श्री राम तथा आर नोय अन्नाय (और अन्याय नहीं) के नारे लगा रहे थे। बरुईपुर का रोडशो एक किलोमीटर लंबा था जबकि आरामबाग का रोडशो 1.5 किलोमीटर का था।

संघचालक मोहन भागवत संस्कार भारती कला संकुल का लोकार्पण

नई दिल्ली, (संवाददाता)। संस्कार भारती द्वारा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बनाए गए कला संकुल (परिसर) का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत द्वारा किया जाएगा। यह उद्घाटन समारोह पद्मश्री हरिभाऊ वाकणकर जयंती की पूर्वसंध्या पर होगा। कला साहित्य रंगमंच के लगभग 1000 कलाकार, संस्कृतिकर्मी, कलागुरु एवं अन्य विद्वतजनो के उपस्थित रहने की संभावना है। चार मंजिला कला संकुल मुख्य रूप से कला-संस्कृति गतिविधियों का परिसर है, जिसमे कला साहित्य रंगमंच सहित अनेक विधाओं का संयोजन व संवर्धन किया जायेगा। इसमें कला-संस्कृति की पुस्तकों से सुसज्जित एक समृद्ध पुस्तकालय, आर्ट गैलरी, सभागार, स्टूडियो एवं कांफ्रेंस रूम की सुविधा उपलब्ध है। संस्कार भारती आगामी भविष्य में दिल्ली को एक कला नगर का रूप स्थापित करना चाहता है, जिसकी सांस्कृतिक सुगंध से पूरा देश सुवासित हो और भविष्य में कला संकुल कला-संस्कृति के बड़े केंद्र के रूप में जाना जाएगा। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहनराव भागवत है। समारोह में संस्कार भारती के संरक्षक पद्मश्री बाबा योगेंद्र, संस्कार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष वासुदेव कामत, राज्यसभा सदस्य पद्मविभूषण डॉ सोनल मानसिंह, लोकगायका पद्मविभूषण तीजनबाई, लेखक चिंतक पद्मश्री नरेंद्र कोहली, मणिपुरी नर्तक पद्मभूषण राजकुमार सिंहजीत सिंह एवं गायक पद्मभूषण पडित राजन मिश्र का विशेष सानिध्य रहेगा। कार्यक्रम के संयोजक अनुपम भटनागर, एवं सहसंयोजक भूपेंद्र कौशिक होंगे। भारती एक राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संगठन है, जो भारत की परम्परागत शास्त्रीय, लोक और आधुनिक कलाओं के माध्यम से लोक जीवन में राष्ट्रीय मूल्यों के बीजारोपण के लिए प्रयत्नशील है।

कार्टून

पंजाब में ज्यादा काम करवाने के लिए बिहार-यूपी के मजदूरों को दिए जाते हैं ड्रग्स : गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, (संवाददाता)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को पत्र लिखा है जिसमें राज्य के सीमावर्ती गांवों में किसानों के साथ काम करने वाले बंधुआ मजदूरों की एक गंभीर समस्या पर विचार करने के लिए कहा है। इस मामले से जुड़े लोगों ने इसकी जानकारी दी है। गृह मंत्रालय ने जिन मजदूरों को लेकर चिंता जताई है, उनमें अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये बंधुआ मजदूर अच्छे वेतन के वादे पर पंजाब में काम करने के लिए अपने घर से से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाते हैं। लेकिन, पंजाब पहुंचने के बाद उनका शोषण किया जाता है। खराब भुगतान किया जाता है। 17 मार्च को पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को लिखे गए पत्र के अनुसार इस अमानवीय व्यवहार के बारे में पता चला है। मंत्रालय ने कहा कि बंधुआ मजदूरों को अक्सर ड्रग्स दिया जाता है, जिससे उन्हें खेतों में लंबे समय तक काम करने में मदद मिलती है। इससे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ती है। मंत्रालय ने कहा समस्या ध्यान में रखते हुए, जिसमें मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और मानवाधिकारों का उल्लंघन शामिल है, आपसे अनुरोध है कि इस मामले को देखें और इसके समाधान के लिए उचित कदम उठाएं। राज्य सरकार से इस मामले पर प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय को इस मामले को चिह्नित किया है, जिसमें सभी राज्यों विशेष रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा को विभिन्न स्तरों पर जागरूकता पैदा करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने को कहा है। राज्यों को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बेहतर रोजगार की संभावनाओं और पारिश्रमिक आदि के लिए झूठे वादे करके गरीब और कमजोर पीड़ितों को बेईमान तत्वों द्वारा धोखा दिया जाता है। 2019 और 2020 में पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर और अबोहर के सीमावर्ती गांवों से पकड़े गए लोगों के आधार पर परेशान करने की प्रवृत्ति का विवरण साझा किया गया है। सीमा सुरक्षा बल ने इन दोनों जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों से 58 भारतीय नागरिकों को पकड़ा है। गृह मंत्रालय ने पत्र में लिखा है, पूछताछ के दौरान, यह सामने आया कि उनमें से ज्यादातर या तो मानसिक रूप से विकलांग थे या मानसिक रूप से कमजोर थे।

संक्षिप्त समाचार

टॉफी देकर मांग रहा वोट, पाकिस्तान में चुनाव प्रचार के इस अनूठे तरीके को देख आप भी कहेंगे, भई वाह!

लाहौर । चुनावों में जीतने के लिए आपने एक से चुनाव प्रचार के तरीके देखे होंगे. मगर इस उम्मीदवार का अंदाज थोड़ा जुदा है. अब चुनावों में जीत मिलेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा. मगर इस प्रत्याशी ने अपने प्रशंसकों का दिल तो जीत ही लिया है. हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कराची में हो रहे उप चुनावों में किस्मत आजमा रहे मिफ्ता इस्माइल की. इस्माइल नवाज शरीफ की पार्टी क्क्र-ह के प्रत्याशी हैं. पेशे से वह एक कैंडीमेकर हैं. इस्माइल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मिफ्ता इस्माइल हैं. कैंडीलैंड और बिस्कोनी नाम की कंपनी इसी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती है. इस्माइल ने अपने वोटरों को लुभाने के लिए अनूठा तरीका अपनाया और उन्होंने अपनी तस्वीर और निर्वाचन क्षेत्र वाली कैंडी ही बाजार में उतार दी है. कैंडी के छोटे से पैक के एक और उनका नाम 'मिफ्ता' और उनकी तस्वीर है. दूसरी ओर ह्र-249 चुनाव क्षेत्र और उनकी पार्टी का नाम लिखा है.

सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ- सोशल मीडिया पर इस अनूठे तरीके की काफी तारीफें हो रही हैं. बहुत से यूजर्स उन्हें एक स्मार्ट उम्मीदवार मान रहे हैं. जबकि कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं. मिफ्ता इस्माइल ने भी प्रचार के कई ट्वीट को री-ट्वीट किया है.

कौन है मिफ्ता इस्माइल- मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तान के जाने-माने बिजनेसमैन हैं. साल 2018 में वह पाकिस्तान के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं. इससे पहले भी वह कई शीर्ष पदों पर रह चुके हैं. इस्माइल पाकिस्तान निवेश बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं. साथ ही आईएमएफ और विश्व बैंक के साथ भी वह जुड़े रहे हैं. वह 2011 से नवाज शरीफ की पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं. कराची की ह्र-249 सीट पर 29 अप्रैल को उप-चुनाव होने हैं. इस सीट के लिए नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 7 अप्रैल है. इमरान खान की पार्टी पीटीआई के फैजल वावदा इस सीट से चुनाव जीते थे. मगर 3 मार्च को सीनेट चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उन्होंने यह सीट छोड़ दी थी. नवाज शरीफ की पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी से भी समर्थन मांगा है.

रूस ने पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को 'सबसे निचले स्तर पर' बताया, बाइडेन के 'हत्यारा' कमेंट से बढ़ा तनाव

वाशिंगटन । रूस की पश्चिमी देशों के साथ दूरी पर एक बार फिर बढ़ रही है. यहां के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार को कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ उनके देश के संबंध 'सबसे निचले स्तर' पर पहुंच गए हैं और रूसी राजदूत को वापस वाशिंगटन भेजने के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है. रिश्तों में कड़वाहट उस समय और बढ़ गई, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 'हत्यारा' कहा था. बाइडेन से एक साक्षात्कार में पूछा गया था कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 'हत्यारा' हैं और उन्होंने जवाब दिया था, 'मैं मानता हूं.' उसके बाद रूसी राजदूत को वापस बुला लिया गया था. फिर गुरुवार को इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने बाइडेन की टिप्पणी को 'घटिया' बताया और कहा कि उन्होंने मास्को को वाशिंगटन के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है .

लावरोव ने जताया खेद-लावरोव ने तनाव कम करने में मदद के लिए बाइडेन के साथ संवाद के पुतिन के प्रस्ताव को अमेरिका द्वारा खारिज किए जाने पर खेद व्यक्त किया था. लावरोव ने कहा कि यह तय करना पुतिन के हाथ में है कि राजदूत अनातोली एंटोनोव वाशिंगटन कब लौटेंगे. इस मुद्दे पर पुतिन की ओर से भी जवाब आया था. वह क्रीमिया को 2014 में रूस में मिलाए जाने की सालगिराह पर वहां के निवासियों को वीडियो के माध्यम से संबोधित कर रहे थे.

पुतिन ने मामले में क्या कहा- इसी दौरान पुतिन से पूछा गया था कि वह बाइडेन की टिप्पणी पर क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि यह अमेरिका के इतिहास को दिखाती है. पुतिन ने अमेरिका के गुलामी के इतिहास की ओर इशारा करते हुए कहा था, ब्लैक लीव्स मैटर आंदोलन कहां से आता है? पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि बाइडेन की टिप्पणी बेहद खराब है और वह रिश्तों को सामान्य नहीं करना चाहते हैं. इसके साथ ही उन्होंने कार्रवाई करने तक की बात कही थी.

उत्तर कोरिया में रहना हुआ मुश्किल, देश छोड़कर जा रहे राजनयिक और विदेशी नागरिक

वाशिंगटन । उत्तर कोरिया इस समय कई परेशानियों का सामना कर रहा है, बावजूद इसके दुनिया के सामने उसकी अकड़ बरकरार है. यहां रूस के दूतवास ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर देश दवाइयों और जरूरी वस्तुओं की घोर कमी का सामना कर रहा है. उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि उसके यहां संक्रमण के मामले नहीं हैं और उसने संक्रमण से बचाव के प्रयासों के तहत अपनी सीमाओं को बंद किया हुआ है.

राजनयिक और विदेशी नागरिक लगातार देश छोड़कर जा रहे हैं. मार्च के महीने में संयुक्त राष्ट्र के दो कर्मचारियों ने कथित तौर पर देश छोड़ दिया था. दोनों विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए काम करते थे. रूसी दूतावास ने गुरुवार को फेसबुक पोस्ट में कहा कि 18 मार्च को उत्तर कोरिया छोड़ने वाले 38 विदेशी नागरिकों ने चीन से लगते सीमाई शहर डानडोंग में दो सप्ताह का आइसोलेशन पूरा किया, साथ ही कहा कि विदेशियों को 'निकाला' जाना जारी रहेगा.

केवल 290 विदेशी नागरिक बचे- दूतावास ने कहा, 'कोरियाई राजधानी से जाने वालों के बारे में समझा जा सकता है. हर कोई पाबंदियों को नहीं सह सकता, जो अप्रत्याशित तौर पर बहुत कठोर हैं. दवाइयों सहित जरूरी सामानों की घोर कमी है और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में भी दिक्कतें आ रही हैं.' दूतावास ने साथ ही कहा कि प्योंगयांग में 290 से कम विदेशी नागरिक बचें हैं. ऐसे में ये भी जल्द ही यहां से जा सकते हैं. दुनियाभर के देशों ने कोरोना वायरस के आंकड़े साझा किए हैं, लेकिन उत्तर कोरिया ने अभी तक एक बार भी आंकड़े जारी नहीं किए हैं.

संक्रमण रोकने के लिए क्रूर तरीके- इससे करीब एक महीने पहले खबर आई थी कि उत्तर कोरिया कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्रूर तरीके अपना रहा है. वह मानवाधिकारों का उल्लंघन भी कर रहा है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं ने इसे लेकर कहा था कि चीन से लगने वाली सीमा को बंद कर दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधित है और घरेलू स्तर पर लोगों की आवाजाही पर रोक है. जिसके कारण यहां के लोगों का दुनिया से अधिक कटाव हो गया है. लोगों को रोजमर्रा का सामान भी नहीं मिल पा रहा है.

सुरंग के भीतर पटरी से उतरने के बाद दीवार से टकराई यात्रियों से भरी ट्रेन, 34 लोगों की मौत

वाशिंगटन । ताइवान में शुक्रवार को सुरंग के भीतर यात्रियों से भरी एक रेल पटरी से उतर गई. जिससे अभी तक 36 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं. इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी है . इनका कहना है कि अभी भी कुछ लोगों के शव सुरंग के अंदर ही हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है. घटना की जानकारी मिलते ही यहां बचाव दल पहुंचा है, जो लोगों को बाहर निकाल रहा है. ऐसी आशंका है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है. हादसे के समय रेल में 350 यात्री सवार थे. ये रेल ताइतुंग की ओर जा रही थी, लेकिन अचानक पटरी से उतर गई. फिर सुरंग के भीतर ही रेल की टक्कर दीवार से हो गई. बयान में कहा गया है, 'प्राथमिक तौर पर ऐसा लग रहा है कि कई लोगों की मौत हुई है.' हादसा ऐसे समय में हुआ है, जब सालाना टॉम्ब स्वीपिंग फेस्टिवल के कारण लंबी छुट्टियां चल रही हैं. इस दौरान ताइवान की सड़क से रेलवे तक सब व्यस्त रहता है.

ट्रेन के ऊपर गिरा ट्रक

ताइवान की पूर्वी रेलवे लाइन पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है. बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने आते हैं. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक ट्रक ऊपर से नीचे गिरा, उस समय रेल सुरंग से गुजर रही थी. तस्वीर में भी ट्रक को रेल के पास पड़ा हुआ देखा जा सकता है. अभी तक रेल सुरंग के भीतर ऐसे ही फंसी हुई है. जिसके कारण यात्रियों को जान बचाने के लिए खिड़कियों, दरवाजों और रेल की छत का सहारा लेना पड़ रहा है. बचाव दल के अनुसार, ट्रक के गिरने से रेल को काफी क्षति पहुंची है. घटना के वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं.

अफगानिस्तान में अमन के लिए रूस तत्पर, विदेशी मंत्री लॉवरोव पाकिस्तान का दौरा कर करेंगे अफगान शांति प्रक्रिया पर चर्चा

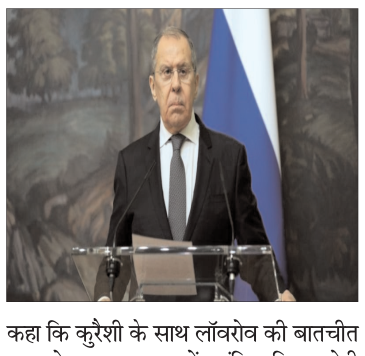

इस्लामाबाद । रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लॉवरोव 6 से 7 अप्रैल तक पाकिस्तान की यात्रा पर होंगे. इस दौरान वह अपने पाकिस्तानी समकक्ष शाह महमूद कुरैशी संग बात करेंगे और अफगान शांति प्रक्रिया, काउंटर टेररिज्म सहयोग और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे. लॉवरोव पाकिस्तान दौरे से पहले भारत की यात्रा पर भी आने वाले हैं. रूसी विदेश मंत्री 4-5 अप्रैल को नई दिल्ली की यात्रा करेंगे.

रूसी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को दो दिवसीय यात्रा की घोषणा की. मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, विदेश मंत्री आर्थिक सहयोग और काउंटर टेररिज्म सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे. पाकिस्तान की यात्रा से पहले, लॉवरोव 5 और 6 अप्रैल को भारत का दौरा करेंगे. यहां वह विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन के लिए जमीन तैयार करेंगे. साथ ही द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे.

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि कुरैशी के साथ लॉवरोव की बातचीत का फोकस अफगान में शांति प्रक्रिया होगी और विभिन्न क्षेत्रों में पाकिस्तान और रूस के बीच सहयोग में सुधार करना होगा. उन्होंने कहा कि लॉवरोव अफगानिस्तान में रूसी विदेश दूत जमीर काबोलुव के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे. काबोलुव ने इससे पहले फरवरी में पाकिस्तान का दौरा किया था और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की थी.

इस्लामाबाद और मॉस्को के संबंधों में हुआ है सुधार- रूसी विदेश मंत्री की ये दुर्लभ यात्रा ऐसे समय पर हो रही है, जब इस्लामाबाद और मॉस्को के बीच संबंधों में हाल के वर्षों में सुधार देखने को मिला है. रूस ने हाल ही में शांति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के प्रयासों के तहत पाकिस्तान, अमेरिका, चीन और अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों और तालिबान प्रतिनिधियों वाले एक सम्मेलन की मेजबानी की. रूस अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया के लिए पाकिस्तान को अहम मानता है.

4-5 अप्रैल को भारत दौरे पर आएंगे लॉवरोव- वहीं, रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता में कहा, 4-5 अप्रैल को विदेश मंत्री सर्गेई लॉवरोव भारत की सरकारी यात्रा पर जाएंगे. इस यात्रा के दौरान वह अपने भारतीय समकक्ष (एस जयशंकर) से वार्ता करेंगे. यात्रा के दौरान दोनों मंत्री द्विपक्षीय संबंधों और दोनों देशों के शासनाध्यक्षों की आसन्न बैठक की तैयारियों के बारे में चर्चा करेंगे. लॉवरोव की भारत यात्रा तब हो रही है जब कुछ ही समय पहले भारत के विदेश सचिव ने रूस की यात्रा की थी.

बांग्लादेश में रोहिंग्या कैंप के पास बाजार में लगी भीषण आग, 20 दुकानें जलकर खाक, तीन की मौत

वाशिंगटन , एजेंसी । बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक बाजार में भीषण आग लग गई है. ये बाजार रोहिंग्या कैंप्स के पास है. हादसे में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई है. शुक्रवार को लगी इस आग में 20 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गईं. इस घटना की जानकारी पुलिस और गवाहों ने दी है. स्थानीय पुलिस प्रमुख अहमद सांतुर मुर्शीद ने कहा कि दमकलकर्मियों को आग काबू करने में घंटों का समय लग गया. जिसके बाद मलबे से शवों को बाहर निकाला गया.

आग शुक्रवार तड़के लगी थी, जिसके कारण शिविरों में सो रहे रोहिंग्या उठ गए. एक दुकान के मालिक सइदुल मुस्तफा की मौत हो गई है. हालांकि अभी तक आग लगने के पीछे का कारण पता नहीं चल सका है. अभी एक हफ्ते पहले भी कैंप में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी और 560 अन्य लोग घायल हुए थे. इसके साथ ही 45 हजार लोगों को बेघर होना पड़ा है.

बालुखली कैंप में लगी थी आग- बीते महीने लगी ये आग देश के उत्तरी हिस्से में स्थित रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप में लगी थी. आग कॉक्स बाजार जिले के बालुखली कैंप में लगी थी. कम से कम चार ब्लॉक्स आग की चपेट में आ गए थे. उस समय सरकार के शरणार्थी, राहत और प्रत्यावर्तन आयोग के अतिरिक्त आयुक्त मोहम्मद शमसुद दौजा ने कहा था कि आग को काबू में करने के लिए दमकलकर्मियों की चार यूनिट को लगाया गया था.

म्यांमार से आए थे रोहिंग्या- इस समय बांग्लादेश में लाखों की संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं. ये लोग साल 2017 में म्यांमार की सेना से अपनी जान बचाकर यहां आए थे. इनपर सेना ने खूब अत्याचार किया था. रोहिंग्या मुस्लिमों का नरसंहार किया गया, इनके घरों को आग लगा दी गई और महिलाओं के साथ तक बलात्कार किया गया. सेना से बचने के लिए ये लोग पड़ोसी देशों की ओर भागे थे और इनकी सबसे बड़ी संख्या बांग्लादेश में आकर रहने लगी. इन लोगों के रहने के लिए बांग्लादेश ने शिविरों की व्यवस्था की है.

डब्ल्यूएचओ प्रमुख द्वारा सुझाई अंतरराष्ट्रीय संधि के पक्ष में आए कई देश, भविष्य के खतरे की होगी रोकथाम

न्यूयॉर्क (संयुक्त राष्ट्र)। दुनिया की कई बड़ी हस्तियों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टैड्रॉस ऐडहेनॉम घेबरेयेसस के उस प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया है जिसमें उन्होंने भविष्य में आने वाली महामारियों के खतरे को देखते हुए एक अंतरराष्ट्रीय संधि की वकालत की है। संगठन के प्रमुख का कहना है कि इस संधि पर अंतिम फैसला विश्व के देशों को अपने स्तर पर लेना है, लेकिन यदि भावी पीढ़ी को हम एक बेहतर दुनिया देना चाहते हैं तो ये संधि जरूरी है।

अब भविष्य की इस संधि को लेकर आम राय बनती दिखाई दे रही है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख का समर्थन करने वालों में 25 देश शामिल हैं। इसके अलावा कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी इसको सही और जरूरी बताया है।

संयुक्त राष्ट्र की खबर के मुताबिक ये सहमति कुछ दिन पहले प्रकाशित एक ओपन आर्टिकल के जरिए जताई गई है। ये लेख दुनिया के कई अखबारों में प्रकाशित हुआ था जिसमें कई देशों की हस्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए थे। इस संयुक्त लेख में कहा गया था कि कोरोना महामारी के दौर में जब तक एक भी व्यक्ति असुरक्षित है तब तक सभी लोग सुरक्षित नहीं कहे जा सकते हैं। इसमें ये भी कहा गया था कि भविष्य में इस तरह की महामारियां और स्वास्थ्य आपदाएं आ सकती हैं।

इसमें ये भी कहा गया था कि भविष्य में महामारियों का एकजुट होकर पता लगाने, उनकी रोकथाम करने और उनका विश्लेषण तेजी से करने में हाई क्वालिटी का तालमेल दिखाना होगा। इस आर्टिकल में दुनिया की बड़ी हस्तियों ने अपने विचार पेश किए थे। इसमें लिखा था विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख द्वारा सुझाई गई अंतरराष्ट्रीय संधि इसी संगठन के संविधान से जन्म लेगी और इसका मकसद भविष्य में आने वाली महामारियों को रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय करना होगा। साथ ही इसका मकसद एक ऐसी ढांचागत व्यवस्था कायम करना होगा जिसमें ये संधि अपने मकसद में कामयाब हो सके।

डब्ल्यूएचओ प्रमुख के अंतरराष्ट्रीय संधि के पक्ष का समर्थन करने वालों में सेनेगल, सर्बिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, अल्बानिया, चिली, कोस्टा रीका, योरोपीय काउंसिल, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इंडोनेशिया, इटली, केन्या, नीदरलैंड, नॉर्वे, थाईलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो, ट्यूनीशिया, ब्रिटेन, पुर्तगाल, कोरिया गणराज्य, रोमानिया, रवांडा और यूक्रेन के प्रतिनिधि शामिल थे। इन सभी का कहना था कि वैश्विक महामारी कोविड-19 ने दुनिया में अलग-थलग पड़ी शक्तियों के विभाजन का पूरा फायदा उठाया है, लेकिन अब इस तरह की महामारियों को इस तरह से फायदा उठाने का मौका दोबारा नहीं देना चाहिए। आज इस महामारी को लेकर पूरा विश्व एक है उनकी सोच एक है। इसका अंतरराष्ट्रीय जगत को पूरा फायदा उठाना चाहिए और भविष्य के निए काम करना चाहिए। सभी देशों को भविष्य में भी एकजुट होकर काम करना होगा वो भी बिना समय गंवाए।

दक्षिण अफ्रीका में गुप्ता बंधुओं की बढ़ी मुश्किलें, सहारा कंप्यूटर्स के बैंक खाते से करोड़ों रुपये की राशि जब्त

जोहानिसबर्ग । दक्षिण अफ्रीका के सेंट्रल बैंक ने गुप्ता भाइयों के स्वामित्व वाली कंपनी सहारा कंप्यूटर्स के बैंक खाते से 13 लाख डॉलर (9.52 करोड़ रुपये) से अधिक की राशि जब्त की है। सेंट्रल बैंक (एसएआरबी) के डिप्टी गवर्नर कुबेन नायडू ने सरकार के राजपत्र में एक नोटिस प्रकाशित कर इसकी जानकारी दी। नोटिस में कहा गया कि नेडबैंक खाते में जमा राशि और उस पर मिले ब्याज को सरकार ने जब्त कर लिया है।

एसएआरबी ने कंपनी के एक स्थानीय बैंक खाते से लगभग 200 लाख रैंड यानी 13 लाख डॉलर जब्त किए हैं। सहारा कंप्यूटर्स गुप्ता बंधुओं अजय, अतुल और राजेश द्वारा शुरू की गई पहली बड़ी आइटी कंपनी थी। गुप्ता बंधु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं। वे 1990 के दशक में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की शुरुआत में बस गए। अपनी सफलता के चरम पर सहारा कंप्यूटर, दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख आइटी आपूर्तिकर्ताओं में से एक थी। कंपनी के पास उस समय देश के शीर्ष तीन क्रिकेट स्टेडियमों मे नामकरण अधिकार था और ब्रांड एंबेसडर के रूप में खेल और मनोरंजन के कई प्रमुख व्यक्ति उससे जुड़े थे।

गुप्ता परिवार अब दुबई में रहता है। दक्षिण अफ्रीका, सरकारी संस्थानों से अरबों रैंड की चपत लगाने के मामले में उनकी कथित भूमिका को लेकर पूछताछ करने के लिए प्रत्यर्पण का प्रयास कर रहा है। वर्ष 2016 में कई अवैध सौदों की जानकारी सामने आने के बाद दक्षिण अफ्रीका के बैंकों ने गुप्ता परिवार की कंपनियों के साथ कारोबार करने से मना कर दिया था। गुप्ता भाइयों पर आरोप है कि वे पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के साथ घनिष्ठ संबंधों के जरिये अरबों रैंड की चपत लगाने में शामिल थे। पूर्व राष्ट्रपति जुमा भी अभी आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

भारत, बांग्लादेश और यूएई की यात्रा पर निकले बाइडन के विशेष दूत जॉन कैरी

वाशिंगटन । जलवायु परिवर्तन से जुड़े मामलों पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के विशेष दूत जान कैरी एक से नौ अप्रैल के बीच भारत, बांग्लादेश और यूएई की यात्रा पर रहेंगे। 22-23 अप्रैल के बीच जलवायु परिवर्तन पर आयोजित शिखर सम्मेलन और इस वर्ष के अंत में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी26) से पहले कैरी इस मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए इन देशों की यात्रा करने जा रहे हैं।

इस दौरान होने वाली बातचीत का एजेंडा ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाना है। उनकी इस यात्रा में सबसे दिलचस्प बात ये है कि वो न तो पाकिस्तान जाएंगे और न ही वहां के किसी नेता से बात ही करेंगे। अप्रैल 22-23 में जलवायु सम्मेलन आयोजित करने का ऐलान किया है, जिसमें दुनिया के 40 देशों को आमंत्रित किया गया है लेकिन पाकिस्तान को आमंत्रित भी नहीं किया गया।

विदेश मंत्रालय ने इस बारे में पहले ही संकेत दे दिए थे कि पाकिस्तान को क्लाइमेट समिट से बाहर रखा गया है। अखबार ने इसकी वजह लिखी है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान बेहद कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विश्व के 40 नेताओं को दो दिवसीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। सम्मेलन का मकसद जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के आर्थिक लाभ एवं महत्व को रेखांकित करना है। व्हाइट हाउस ने पिछले सप्ताह कहा था, यह ग्लासगो में इस साल नवंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी26) के मार्ग में मील का पत्थर साबित होगा।

व्हाइट हाउस के अनुसार, शिखर सम्मेलन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन और सीओपी26 का मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के प्रयासों को गति देना है। इस सम्मेलन में वे 17 देश भाग लेंगे, जो वैश्विक स्तर पर 80 फीसद उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं और वैश्विक जीडीपी में उनकी 80 फीसद भूमिका है।

चीन के राज में लोकतंत्र बचाना भी 'पाप', हांगकांग के मीडिया टाइकून समेत सात लोगों को अदालत ने प्रदर्शन करने का पाया दोषी

बीजिंग एजेंसी । हांगकांग में गुरुवार को सात लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया गया है. इन पर आरोप था कि इन्होंने 2019 में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान गैर-कानूनी तरीके से सभा करने और उसमें हिस्सा लिया. इसके अलावा हांगकांग में लोकतंत्र अभियान की अगुवाई करने वाले 82 वर्षीय मार्टिन ली को भी दोषी पाया गया है.

लोकतंत्र समर्थक इन कार्यकर्ताओं को 18 अगस्त, 2019 को हुए प्रदर्शनों में शामिल होने के मामले में दोषी ठहराया गया है. इनमें से कुछ कार्यकर्ताओं को हांगकांग से बाहर ना जाने और अपने यात्रा दस्तावेज सौंपने की शर्त पर जमानत मिल चुकी है. वहीं कुछ अन्य मामलों में अब भी हिरासत में हैं. मामले पर आगे की सुनवाई 16 अप्रैल को होगी, जब सजा कम करने संबंधी याचिका पर सुनवाई की जाएगी और फिर सजा का ऐलान किया जाएगा.

चीन के विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हुआ बवाल- हांगकांग में गैरकानूनी तरीके से एकत्रित होने और दंगा करने के जुर्म में 10 साल तक की सजा हो सकती है. मामले पर सुनवाई से पहले कई समर्थकों ने अदालत के बाहर नारेबाजी भी की थी. उक्त प्रदर्शन के आयोजकों का कहना था कि चीन के एक प्रस्तावित विधेयक (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के खिलाफ उस दिन 17 लाख लोगों ने मार्च निकाला था. इस प्रस्तावित विधेयक में किसी भी आपराधिक मामले के संदिग्ध को सुनवाई के लिए चीन प्रत्यर्पित करने का प्रावधान था.

प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हुई हिंसक झड़प - हांगकांग में 2019 में इस प्रत्यर्पण विधेयक के खिलाफ व्यापक स्तर पर प्रदर्शन किए गए थे. विधेयक को अंततः वापस ले लिया गया था, लेकिन पूर्ण लोकतंत्र और अन्य मांगों को लेकर लोगों ने प्रदर्शन करना जारी रखा और कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसा भी हुई.

चीन के इस विवादित कानून को लेकर उसकी दुनियाभर में आलोचना की गई. इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे जाने और गोलियां चलाने के मामले भी सामने आए थे.

हांगकांग को चीन ने ब्रिटेन से 50 सालो के लिए लिया- सुनवाई से पहले लोकतंत्र समर्थक और बचाव पक्ष के लोग अदालत के बाहर इकट्ठा हुए और उन्होंने जमकर नारेबाजी. 2019 में विवादित कानून को लेकर कई महीनों तक हांगकांग में विरोध प्रदर्शन हुए. चीन ने ये देखते हुए कानून तो वापस ले लिया, लेकिन विरोध प्रदर्शनों जारी रहे. चीन ने 1997 में ब्रिटेन से हांगकांग को लेने पर शहर को 50 साल तक स्वतंत्र रूप से बनाए रखने की वादा किया था, लेकिन इसके हालिया कदमों को एक विश्वासघात के रूप में देखा जाता है.

म्यांमार की सैन्य सरकार ने वायरलेस इंटरनेट बंद करने का दिया आदेश, यूएन ने जारी किया बयान

वाशिंगटन , एजेंसी। म्यांमार की सैन्य सरकार ने 500 से अधिक लोगों की हत्या करने के बाद देश के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से कहा है कि वह अगले आदेश तक वायरलेस ब्रोडबैंड सर्विस को बंद कर दें. इस बात की जानकारी टेलिकॉम से जुड़े सूत्रों ने दी है. एक सेवा प्रदाता को भेजा गया ईमेल लगा है, जिसमें इस आदेश के पीछे का कारण भी नहीं बताया है. इसमें ये भी कहा गया है कि वर्तमान में जारी मोबाइल इंटरनेट पर रोक ऐसे ही लगी रहेगी.

दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति ने गुरुवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर की जा रही हिंसा और सैकड़ों लोगों की मौत की साफ शब्दों में निंदा की है. समिति के सदस्यों ने सेना से संयम बरतने को कहा है. म्यांमार में 1 फरवरी को तख्तापलट किया गया था, जिसे अब दो महीने पूरे हो गए हैं . एक दिन पहले भी कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं और लोगों ने लोकतंत्र को बहाल कर हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा करने की मांग की है.

500 से ज्यादा लोगों की मौत

म्यांमार में एक फरवरी को तख्तापलट के बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की है. पश्चिमी देशों द्वारा सैन्य शासन के खिलाफ पाबंदी के बावजूद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोलीबारी की घटनाएं जारी हैं.

देश के सबसे बड़े शहर यांगून में युवाओं के एक समूह ने प्रदर्शन में मारे गए 500 से ज्यादा लोगों की याद में शोक गीत गाए. इसके बाद उन्होंने जुंटा शासन (सैन्य सरकार) के खिलाफ नारेबाजी की, अपदस्थ नेता आंग सान सू की को रिहा करने और लोकतंत्र को बहाल करने की मांग करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया.

कई जगहों पर छापेमारी हुई

मांडले और अन्य शहरों में भी प्रदर्शनकारी एकत्र हुए हैं. इससे पहले पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की और प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की थी. यांगून में सेना की निवेश इकाई 'म्यांमार इकॉनोमिक होल्डिंग लिमिटेड' की कुछ दुकानों में आग लगा दी गई. प्रदर्शन के शुरुआती दिनों से ही इन दुकानों को निशाना बनाया गया है. करिन प्रांत के कई इलाकों में शनिवार से दर्जनों नागरिकों के मारे जाने और 20,000 से ज्यादा लोगों के विस्थापित होने की भी सूचना मिली है. इलाके में राहत अभियान चलाने वाली संस्था 'फ्री बर्मा रेंजर्स' ने इस बारे में बताया है. स्थानीय मीडिया के मुताबिक करिन की सोने की खदान में हवाई हमले में मंगलवार को 11 लोग मारे गए थे.

पाकिस्तान ने टिकटॉक पर लगे बैन को हटाया, चीनी कंपनी पर लगा था 'अश्लीलता' परोसने का आरोप

कराची । पाकिस्तान ने गुरुवार को चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया. टिकटॉक पर अश्लील कंटेट परोसने का आरोप लगा था और इस कारण ही इस ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. पाकिस्तान द्वारा ये प्रतिबंध तब हटाया गया है जब चीनी कंपनी ने कहा है कि वह अब उदारवादी कंटेट को अपलोड करेगी.

रूढ़िवादी पड़ोसी मुल्क में टिकटॉक हमेशा से ही विवादों में रहा है. इस पर युवाओं को बिगाड़ने का आरोप भी लग चुका है.

देश के उत्तर-पश्चिमी शहर पेशावर में स्थित एक अदालत ने पिछले महीने पाकिस्तान संचार नियामक को ऐप को ब्लॉक करने का आदेश दिया था. अदालत ने टिकटॉक को ब्लॉक करने की वजह इसका पाकिस्तान की गहरी रूढ़िवादी नैतिक मूल्यों के विपरीत होना बताया था. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी के वकील जहांजब महसूद ने कहा कि ऐप ने हमें आश्वासन दिया है कि ये अब एक फिल्टर का प्रयोग करेगा और उदारवादी कंटेट को अपलोड करेगा. पाकिस्तान के ग्रामीण इलाकों और युवाओं में लोकप्रिय है टिकटॉक

इससे पहले चीनी स्वामित्व वाली इस कंपनी ने अक्टूबर में लगे एक और प्रतिबंध के दौरान कहा था कि ये उदारवादी कंटेट को परोसने की तरफ ध्यान देगा. टिकटॉक पाकिस्तान के युवाओं में खासा लोकप्रिय है. इसकी सबसे ज्यादा लोकप्रियता पड़ोसी मुल्क के ग्रामीण इलाकों में है.

प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकारों में से एक ने पहले टिकटॉक पर युवा लड़कियों के शोषण, वस्तूकरण और यौन शोषण को बढ़ावा देने के लिए दोषी ठहराया था. हालांकि, कंपनी ने इन आरोपों से इनकार किया था.

इंटरनेट पर नियंत्रण के लिए होती है पाकिस्तान की आलोचना

वहीं, टिकटॉक ने इस फैसले का स्वागत किया है. 'फ्रीडम ऑफ स्पीच' की वकालत करने वालों ने लंबे समय से सरकार की सेंसरशिप और पाकिस्तान के इंटरनेट एंव प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नियंत्रण की आलोचना की है. पिछले साल पाकिस्तानी रेगुलेटर्स ने YouTube से उन सभी वीडियो को तुरंत ब्लॉक करने को कहा था. जिनको लेकर उनका मानना था कि ये देश के लिए आपत्तिजनक हैं. अधिकारियों के इस फैसले की मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने जमकर आलोचना की थी.

एक नजर

दिल्ली में 12,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती की तैयारी

नई दिल्ली । दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार सहित दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में शिक्षकों की समस्या का जल्द ही समाधान हो जाएगा। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने रिक्त पड़े 12,065 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड ने यह जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट को दी है।

गौरतलब है कि गैर सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया था कि हाई कोर्ट के आदेश के बाजवूद भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इस पर सुनवाई के दौरान डीएसएसएसबी के उप सचिव धर्मेंद्र शर्मा ने हलफनामा दायर किया। इसमें कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में देरी हुई है। 31 मई तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 15 जनवरी 2022 तक परीक्षा ली जाएगी और 31 मार्च तक फाइनल सूची जारी की जाएगी। डीएसएसएसबी द्वारा विभिन्न श्रेणियों के 5,032 पदों पर बहाली के लिए सूचना जारी की जा चुकी है। इसके अलावा दक्षिण निगम के 1,126 विशेष शिक्षकों की भर्ती का अनुरोध पत्र मिल चुका है। इसका 28 फरवरी 2021 व इसके बाद विज्ञापन निकाला जा चुका है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार देश में नई शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने के साथ कई राज्यों में इसे लेकर समितियां भी बनाई गईं हैं। देशभर के सरकारी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हों, इस पर भी जोर दिया जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत देशभर में शिक्षकों के 61 लाख 84 हजार 464 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 10 लाख 60 हजार 139 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों की सबसे ज्यादा कमी बिहार और उत्तर प्रदेश में है। इनके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। मार्च के प्रथम सप्ताह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संसद के पटल पर एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी थी।

श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली । सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इस अवसर पर एक मई को चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में मत्था टेकने के बाद प्रधानमंत्री श्री गुरु तेग बहादुर के स्मारक का लोकार्पण भी कर सकते हैं। इस विशालकाय स्मारक में गुरु के त्याग और बलिदान की जानकारी होगी। सेंट्रल वर्ज पर इसे 40 फीट ऊंचाई और 25 फीट चौड़ाई में बनाया गया है। इसकी मोटाई सात फीट होगी।

जानकार बताते हैं कि जहां शीशगंज गुरुद्वारा है, वहां इस्लाम ग्रहण न करने पर मुगल बादशाह औरंगजेब के कहने पर एक जल्लाद ने श्री गुरु तेग बहादुर के साथ उनके शिष्यों का गला काटा था। इसके पहले उन्हें बादशाह द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए कई प्रलोभन दिए गए और उनके सामने शिष्यों को मौत के घाट उतरवाकर उन्हें डराया भी गया था। इसके बाद भी उन्होंने साफ कहा था कि शीश कटा सकते हैं पर केश नहीं। इसके चलते यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा विश्व भर के लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। केंद्र सरकार ने उनके 400वें प्रकाश पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 70 सदस्यीय कमेटी भी गठित की है। यह कमेटी पूरे देश में प्रकाश पर्व को लेकर विविध कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग कर रही है। एक मई को प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए देशभर के विभिन्न स्थानों से जत्थे शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचेंगे। उस दिन राष्ट्रीय राजधानी में भी जगह-जगह कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पदाधिकारी का कहना है कि एक मई को गुरुद्वारा में बड़े कार्यक्रम की तैयारी है। प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे या नहीं इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

हरदीप पुरी ने लिया तैयारियों का जायजा- प्रकाश पर्व के समापन समारोह को लेकर गुरुद्वारे में तैयारियां चल रही हैं। बृहस्पतिवार को शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के साथ ही गृह मंत्रालय व संस्कृति मंत्रलय के सचिव ने यहां पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ उत्तरी नगर निगम के आयुक्त भी रहे। इस बीच पुरी गुरुद्वारे में करीब एक घंटे तक रुके।

दिल्ली में अब गजेटेड होलिडेज और रविवार को भी नहीं होगी छुट्टी, हर दिन वैक्सीनेशन का आदेश

नई दिल्ली । देशभर में बढ़ते कोरोना मामलों ने एक बार फिर चिंता पैदा कर दी है. इतना ही नहीं कई राज्यों में लग रहे लॉकडाउन के बाद अब वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है. दिल्ली सरकार ने भी हर दिन वैक्सीनेशन को संभव बनाने के लिए आदेश जारी किया है. ऐसे में अब किसी भी दिन कोरोना वैक्सीन सेंटर पर छुट्टी नहीं होगी. दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अब गजेटेड होलिडेज या रविवार की भी छुट्टी नहीं होगी. इन दिनों में भी कोरोना वैक्सीन सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन कराया जा सकेगा. विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि छुट्टी के इन दिनों में भी सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के वैक्सीनेशन सेंटरों पर वैक्सीन लगाई जाएगी. फैमिली वेलफेयर डायरेक्टर मोनिका राणा की ओर से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीडीएमओ को आदेश दिया गया है कि वे जिलों में तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करवाने की व्यवस्था करें. कहा गया है कि केंद्र सरकार के आदेशानुसार अब अप्रैल के महीने में कोई भी गजेटेड होलिडे नहीं होगा बल्कि सेंटरों पर हर दिन वैक्सीन लगाई जाएगी. ताकि देशभर में बढ़ रहे कोरोना मामलों को नियंत्रित करने में मदद मिल सके.

दिल्ली पुलिस में तैनात सिपाही की पत्नी ने की आत्महत्या, इससे पहले बच्चों को किया गंभीर रूप से घायल

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस के सिपाही की पत्नी द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आत्महत्या से पहले सिपाही की पत्नी ने अपने दोनों बच्चों को भी मारने की कोशिश की। फिलहाल दोनों बच्चे गंभीर हालत में फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं। बृहस्पतिवार रात की घटना का पता शुक्रवार को सुबह चला। जागरण संवाददाता से मुताबिक, सिपाही का परिवार घिटोरनी इलाके में रहता है, जबकि सिपाही वसंत विहार थाने में तैनात है। इससे पहले रोहिणी इलाके में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बस चालक ने पत्नी व दो बेटों की गला रेतकर हत्या कर दी और खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है।

जिसमें युवक ने पत्नी व बच्चों की हत्या करने की बात कही है। जानकारी के अनुसार 31 वर्षीय धीरज यादव पत्नी आरती (28), दो बेटे हितेन (6) व अथर्व (3) के साथ नाहरपुर गांव में रहता था। वह संविदा पर डीटीसी के रोहिणी डिपो-2 में बतौर चालक कार्यरत था। उसके पिता महा सिंह यादव व बड़े भाई नीरज भी परिवार के साथ एक ही मकान में अलग -अलग मंजिल पर रहते हैं। बताया जाता है कि धीरज नशे का आदी था। उसकी आदतों के कारण उसे परिवार के संयुक्त आमदनी में भी हिस्सा नहीं मिलता था। उसके दोनों बेटे भी दिव्यांग थे तो उसकी मां सुदेश भी मानसिक रूप से बीमार हैं। इसी बात को लेकर उसका परिवार के सदस्यों व पत्नी के साथ अक्सर विवाद होता रहता था। बुधवार की रात को भी उसका पहले पिता से फिर पत्नी से विवाद हुआ था। इसके बाद सभी लोग सोने चले गए थे।

जगाने गए पिता तो पता चला- धीरज को ड्यूटी पर जाने के लिए हर सुबह उसके पिता महा सिंह ही जगाते थे। गुरुवार की सुबह जब वह उसे जगाने के लिए गए तो कमरे से कोई आवाज नहीं आई। कमरा भी अंदर से बंद था। उन्होंने रोशनदान से झांक कर देखा तो धीरज को पंखे से चुन्नी के सहारे झूलते हुए पाया। उन्होंने शोर मचाकर अपने बड़े बेटे को भी बुलाया और मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो धीरज की पत्नी व दोनों बेटे भी खून से लथपथ पड़े थे। पत्नी के गले, छाती व दोनों बेटे के गले पर चाकू से वार करने के निशान थे। उन्हें अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां चारों को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है।

आप ने पूछा सवाल-भाजपा राज्यों में ड्रिंकिंग एज 21 साल तो दिल्ली में परेशानी क्यों?

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार की ओर से हाल ही में नई एक्साइज पॉलिसी लागू करने को लेकर आम आदमी पार्टी पर विपक्ष लगातार हमलावर है. इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से डिफेंसिव मोड में आ गई है.

आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार विपक्ष पर शराब माफियाओं को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाती आ रही है. वहीं अब उसने विपक्ष खासकर भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केजरीवाल सरकार जब से शराब माफियाओं को दिल्ली में खत्म करने के लिए नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई है तब से भाजपा काफी परेशान है. वह हर रोज इसको लेकर विरोध भी कर रहे हैं.

आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और विधायक आतिशी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा शासित कई राज्यों में लीगल ड्रिंकिंग एज 18 साल निर्धारित की हुई है. वहीं कई राज्यों में यह 21 साल है.

भाजपा शासित राज्यों की बात करें तो गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आदि में तो ड्रिंकिंग एज 18 साल निर्धारित है. लेकिन भाजपा आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से ड्रिंकिंग एज को 21 साल करने के बाद से बवाल मचाए हुए हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा इसलिए विरोध कर रही है कि जब 21 साल की आयु के लोग पब और बार रेस्टोरेंट में आते हैं तो हफ्ता वसूली की जाती है. अगर दिल्ली सरकार ड्रिंकिंग एज को 21 साल कर देती है तो भाजपा की यह हफ्ता वसूली और उससे होने वाली काली कमाई खत्म हो जाएगी.

आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने यह भी गंभीर आरोप लगाए कि अभी तक दिल्ली में बहुत-सी ऐसी जगह है जहां पर दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं, जहां पर सरकारी शराब की दुकान नहीं हैं. इसकी वजह से वहां गैर-कानूनी शराब का गोरखधंधा खूब तेजी से होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि इन शराब माफियाओं से भाजपा की जेब में भारी भरकम काली कमाई जाती है.

एम्स के बाहर तीमारदार खुले में रहने को मजबूर, परेशानी के बीच हो रहा इलाज का इंतजार

नई दिल्ली । एम्स के बाहर रहने वाले तीमारदारों और मरीजों के लिए शीत लहर से बचाने के लिए लगाए गए शेल्टर होम हटा दिए गए हैं। शेल्टर होम हटाए जाने से अस्पताल के बाहर रहने वाले लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं, वहीं आश्रय गृहों का संचालन करने वाले एनजीओ स्पाईएम के कर्मचारियों का कहना है कि यह एक नियमित प्रक्रिया है, जिसमें सर्दी में लगाए गए शेल्टर होम को 15 मार्च तक हटा दिया जाता है।

एम्स के बाहर बने थे करीब 11 शेल्टर होम- दिल्ली सरकार के आश्रय सुधार बोर्ड की ओर से शीतलहर से बचाने के लिए शेल्टर होम बनाए गए। एम्स के बाहर करीब 11 शेल्टर होम बनाए गए थे, जिन्हें अब हटा लिया गया है। बिहार के मुजफ्फरनगर से बेटी का इलाज कराने के लिए दो माह पहले आई रूपा ने बताया कि हर 15 दिन में डाक्टर देखने के लिए बुलाते हैं। ऐसे में घर जाना आसान नहीं था। इसलिए बाहर बने आश्रय घरों में रह रहे थे, पर अब खुले में रहने से अच्छा है कि वे अपने घर वापस चले जाएं।

त्योहार के कारण लेट से हटा आश्रय गृह- वहीं उत्तराखंड के टिहरी से आए कुंदन अपने 12 वर्षीय बेटे को लेकर रह रहे थे, लेकिन अब उन्हें अपने घर वापस जाना होगा। लोगों ने बताया कि 27 मार्च को ही लोग आश्रय गृह हटाने के लिए आए थे, लेकिन त्योहार की वजह से कर्मचारियों ने नहीं हटाया था। एक अप्रैल को सभी शेल्टर होम को हटा दिया गया है। शेल्टर होम में रहने वाले परिवारों का कहना है कि एम्स के बाहर स्थायी तौर पर शेल्टर होम का निर्माण किया जाना चाहिए।

वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में दिल्ली-भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे सीएम केजरीवाल, लंदन के मेयर से मिला न्योता!

(एजेंसी)

नई दिल्ली । लंदन के मेयर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्योता दिया है. मुख्यमंत्री ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है.

उन्होंने कहा है कि उनका लक्ष्य संस्कृति के क्षेत्र में दिल्ली को विश्व नेता और कलाकार के अनुकूल शहर में बदलना है. लंदन के मेयर की ओर से मिले निमंत्रण के बाद अब मुख्यमंत्री केजरीवाल वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में दिल्ली और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. इस वर्ष की थीम 'द फ्यूचर ऑफ कल्चर' है, जो विशेष रूप से पिछले एक वर्ष में लोगों के सामने आई कई विनाशकारी चुनौतियों और कोरोना संकट के मद्देनजर दिल्ली की संस्कृति को एक बार स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी.

बताते चलें कि फोरम में लंदन, टोकियो और न्यूयॉर्क समेत दुनिया भर के 40 शहर शामिल हैं जिनमें से सभी संस्कृति और रचनात्मकता के प्रभाव और महत्व को पहचानते हैं. साथ ही, सार्वजनिक नीति व शहरी नियोजन में इन मूल्यों को शामिल करना चाहते हैं. संस्कृति के डिप्टी मेयर्स और सदस्य शहरों से संस्कृति के प्रमुखों द्वारा भाग लिया जाने वाला वार्षिक शिखर सम्मेलन, फोरम की गतिविधि के केंद्र में है. दिल्ली विश्व के शहरी संस्कृति रिपोर्ट का भी हिस्सा होगी, जो शहरों में संस्कृति पर सबसे व्यापक वैश्विक डेटासेट है.

लंदन के मेयर सादिक खान से मिले निमंत्रण पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 'फ्यूचर ऑफ कल्चर' निश्चित रूप से इस चुनौतीपूर्ण दौर में प्रासंगिक विषय है. जैसा कि अभी दुनिया भर के लोगों ने अलगाव में संघर्ष किया है. यह कला और संगीत ही रहा है, जिसने हमें जुड़े रहने और संकट से निपटने में मदद की है. रचनात्मकता और साझाकरण ने लचीलापन के साथ कोविड-19 से निपटने के लिए उम्मीद और शक्ति प्रदान की है.

महामारी की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों ने सांस्कृतिक अभ्यास के तरीकों को फिर से स्थापित करने के लिए नई चुनौतियां और संभावनाएं पेश की हैं. जब हम वापसी की ओर बढ़ रहे हैं, कला और संस्कृति जीवन और समाज के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

उन्होंने आगे कहा कि एक ऐतिहासिक राजधानी के रूप में विविध कलाओं और विरासत को अपने आप में समेटे दिल्ली हमारी समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने और उसे संरक्षित करने में सबसे आगे रही है. हमारी सरकार शहर को बेहतर आकार देने और संस्कृति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए संस्कृति भूमिका निभाने में दृढ़ता से विश्वास करती है. संस्कृति, शहर के लिए दीर्घकालिक स्थायी समाधान खोजने के लिए अहम चाबी होगी. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कला, संस्कृति और भाषा मंत्री भी हैं और वह कुछ असाधारण पहलों पर काम भी कर रहे हैं. डिप्टी सीएम के नेतृत्व में दिल्ली की कला और संस्कृति टीम राजधानी के सांस्कृतिक परिदृश्य को बदलने, ज्ञान का लोकतंत्रीकरण करने, सांस्कृतिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने और सरकारी खर्च का विकेंद्रीकरण करने के लिए कार्यक्रम शुरू करने पर काम कर रही है.

दिल्ली के एक इलाके में 42 साल बाद दो एकड़ में दिखेगा तालाब, पास में बनेगा बच्चों का पार्क

पूर्वी दिल्ली । जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने में तालाबों की अहम भूमिका रहती है। इसी कड़ी में गाजीपुर गांव में पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 'से अर्थ' नामक संस्था के साथ मिलकर दो एकड़ में फैले तालाब (जोहड़) के जीर्णोद्धार की कवायद शुरू कर दी है।

जीर्णोद्धार कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) की मदद से करवाया जा रहा है। इसके लिए निगम ने एक योजनाएं बनाई है, जिसमें तालाब को तैयार करने के बाद आसपास के खाली मैदान में बच्चों के लिए पार्क को तैयार करवाया जाएगा। क्षेत्र में नाले व बरसात के पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की मदद से शुद्ध कर तालाब में डाला जाएगा।

पार्षद अपर्णा गोयल ने बताया कि गांव के बुजुर्गो के अनुसार यहां करीब 42 साल पहले तालाब हुआ करता था। पहले गांव का सारा पानी इसी तालाब में जमा होता था, जिससे आसपास भूजल स्तर काफी अच्छा रहता था। जैसे-जैसे गांव का विकास शुरू हुआ, तो तालाब में क्षेत्र का पानी जाना बंद हो गया। ऐसे में तालाब देखरेख के अभाव में सूख गया।

लोग यहां अपने घरों का कूड़ा व मलबा डालने लगे। कूड़े की गंदगी से लोगों को परेशानी होने लगी। निगम ने लोगों की परेशानी को देखते हुए इस तालाब को पार्क में तब्दील कर दिया है। लेकिन अब जल संरक्षण व भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए निगम 'से अर्थ' के साथ मिलकर तालाब का जीर्णोद्धार कर रहा है।

तालाब में एसटीपी का डाला जाएगा पानी- 'से अर्थ' संस्था के सदस्य मोहित रेनन ने बताया कि इस दो एकड़ जमीन के एक छोर में तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए मिनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) तैयार करवाया जाएगा। प्लांट में क्षेत्र की नाली व बड़े नालों का पानी लिया जाएगा। गंदे पानी को एसटीपी से शुद्ध कर तालाब में डाला जाएगा।

एमसीडी पार्कों में जल बोर्ड ने बंद किये बोरवेल! भाजपा नेता बोले-एनजीटी के आदेशों का हो रहा गलत प्रयोग

नई दिल्ली । दिल्ली के पार्कों की बदहाली को लेकर अब आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है. आम आदमी पार्टी जहां भाजपा शासित निगम को कटघरे में खड़ी कर रही है. वहीं, भाजपा नेता आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर आरोप लगाकर बचाव करने में जुटे हुए हैं. भाजपा नेता आरोप लगा रहे हैं कि एनजीटी के आदेशों की आड़ में दिल्ली जल बोर्ड निगम पार्कों में लगे बोरवेल को सील कर रहा है. इसकी वजह से पार्कों में हरियाली बनाए रखना मुश्किल हो गया है. एनजीटी के फैसले को लेकर अब साउथ दिल्ली नगर निगम ने जल बोर्ड की इस कार्रवाई को रुकवाने के लिये एनजीटी का दरवाजा खटखटाया है.

एसडीएमसी के नेता सदन नरेन्द्र चावला ने कहा कि आप आदमी पार्टी द्वारा नगर निगमों पर पार्कों के रख-रखाव को लेकर झूठे आरोप लगाये जा रहे है. यह दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि निगम पार्कों तक शोधित जल पहुंचाये.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार सम्पूर्ण दिल्ली में जल बोर्ड द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमे कि सभी बोरवेल को सील किया जा रहा. इस निर्णय के खिलाफ दक्षिणी निगम ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में याचिका दायर की और दिल्ली जल बोर्ड को भी कई पत्र लिखे.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपने पिछले आदेश में यह स्पष्ट किया है कि यह दिल्ली सरकार सुनिश्चित करेगी कि नगर निगमों के पार्कों तक पानी की सप्लाई निरंतर जारी रहे. दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है और उल्टा नगर निगमों पर निराधार आरोप लगा रही है.

दक्षिणी निगम अपने लगभग 6000 पार्कों का बेहतर तरीके से रख-रखाव करने का प्रयास कर रहा है. लेकिन पर्याप्त पानी के अभाव में ऐसा करना अत्यंत मुश्किल हो चला है. इसलिए हम दिल्ली जल बोर्ड और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पास भी गये.

उधर, दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि एन.जी.टी. के इस संदर्भ में सबसे ताजा 26 मार्च 2021 के आदेश के पाइंट 2 में साफ कहा गया है कि दिल्ली जल बोर्ड अपने एस.टी.पी. से नगर निगमों को अपने खर्चे पर टैंकर व्यवस्था कर पार्कों की सिंचाई के लियें निःशुल्क जल उपलब्ध करायेगा. जल बोर्ड को एस.टी.पी. से पार्कों तक निःशुल्क पाईप लाईन भी डालनी होगी.

दिल्ली भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि यह दुःखद है कि आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने संवैधानिक संस्था एन.जी.टी. के आदेश को गलत पढ़ कर गलत दर्शाने की कोशिश की जो निंदनीय है और हम इसे एन.जी.टी. प्रमुख के संज्ञान में लायेंगे. बेहतर होगा की गलत ब्यानी करने की जगह आम आदमी पार्टी नेता नगर निगमों के फंड जारी करें ताकि निगम अपने पार्कों का और बेहतर रख रखाव कर सकें. दिल्ली में तीनों नगर निगमों के अंतर्गत लगभग 15500 पार्क हैं. और सौरभ भारद्वाज को मालूम होना चाहिए इनमें से 1000 से कम आर.डब्लू.ए. के रख रखाव में हैं.

किसान प्रदर्शनकारियों ने एनएचएआइ की लाखों की बिजली इस्तेमाल की, 25 लाख रुपये के फूंक डाले तार

नई दिल्ली/गाजियाबाद । तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान प्रदर्शनकारी नवंबर के अंतिम सप्ताह से यूपी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। पिछले 4 महीने से भी अधिक समय से यूपी बॉर्डर पर डटे किसान यहां पर मौजूद संसाधनों का भी जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसान प्रदर्शनकारी यहां हाइवे पर लगी स्ट्रीट लाइटों के खंभों से ही दैनिक उपयोग के लिए बिजली का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आलम यह है कि किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई बिजली का एनएचएआइ अभी तक जहां लाखों रुपये का बिल भर चुकी है वहीं, प्रदर्शनकारियों द्वारा ओवरलोड के चलते करीब 25 लाख रुपये कीमत का केबिल भी फुंक चुका है।

खंभों के सर्किट में तार जोड़कर बिजली का कर रहे इस्तेमाल-

गर्मियां शुरू होने के साथ ही कृषि कानून विरोधियों के यूपी गेट पर चल रहे धरने में बिजली को लेकर आए दिन हाय-तौबा मच रही है। प्रदर्शनकारी एनएचएआइ की ओर से लगी स्ट्रीट लाइट के खंभों के सर्किट में तार जोड़कर बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं।

अवैध रूप से बिजली इस्तेमाल कर चलाया जा रहा कूलर और पंखा- इससे पहले सर्दी के मौसम के दौरान प्रकाश व्यवस्था के अलावा कपड़े धोने की मशीन, कपड़ों की प्रेस, मोबाइल फोन चार्ज के अलावा अन्य दैनिक उपयोग किया जाता था। अब गर्मियों में बड़े कूलर, पंखे के अलावा अन्य इस्तेमाल के लिए बिजली इस्तेमाल की जा रही है।वहीं, अधिक विद्युत भार के चलते अभी तक स्ट्रीट लाइट के लिए डाली गई करीब पांच किलोमीटर लंबी केबिल फुंक चुकी है, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई जा रही है। वहीं, चार माह से अधिक समय से बिजली का इस्तेमाल कर रहे प्रदर्शनकारियों की बिजली के बिल का भुगतान एनएचएआइ कर रहा है। इस घाटे से निपटने के लिए विभाग की ओर से अपने विभाग के अलावा शासन-प्रशासन को अवगत भी कराया गया है।

एनएचएआइ दिन में करेगा आपूर्ति बंद- यूपी गेट पर कृषि कानून विरोधी धरने पर स्ट्रीट लाइट से विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं। चार माह हो चुके हैं अब इस नुकसान से पीछा छुड़ाने के लिए दिन में आपूर्ति बंद करेगा। शाम के समय स्ट्रीट लाइट के लिए आपूर्ति खोली जाएगी। ताकि बिजली का अधिक बिल न बने और अधिक विद्युत भार से केबल व अन्य विद्युत उपकरणों का नुकसान न हो।

वहीं, मुदित गर्ग (परियोजना निदेशक, एनएचएआइ) का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) का काम हाइवे बनाना और उसका रखरखाव करना है। यूपी गेट पर कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे धरने से एनएचएआइ को अभी तक लाखों रुपये का नुकसान हो चुका है। स्ट्रीट लाइट के सर्किट में तार जोड़कर लाखों रुपये की बिजली और करीब पांच किलोमीटर लंबी 25 लाख रुपये की केबिल फुंक चुके हैं। इसके लिए योजना तैयार की जा रही है।

कोरोना ही नहीं इन चीजों का भी खौफ सता रहा दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को, आप भी रहें सतर्क

नई दिल्ली । बेशक दिल्ली मेट्रो रेल निगम अपने यात्रियों को विश्वस्तरीय सेवाएं मुहैया कराता है, लेकिन बीच-बीच में कुछ खामियों की शिकायत लोग करते रहते हैं। इसी कड़ी में मेट्रो यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया के जरिये डीएमआरसी से उसकी एक बड़ी खामी की ओर इशारा किया है। लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर शिकायत की है कि इन दिनों मेट्रो यात्रा के दौरान ट्रेनों में मच्छर काट रहे हैं, ऐसे में उन्हें मलेरिया और डेंगू होने का डर सता रहा है। मेट्रो में काट रहे मच्छरों को लेकर लोग इंटरनेट मीडिया पर डीएमआरसी से शिकायत भी कर रहे हैं।

दिल्ली मेट्रो में मच्छरों ने बढ़ाई मुश्किलें- यात्रियों का कहना है कि मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच मच्छरों का प्रकोप अधिक हो गया है। इन दिनों स्थिति यह बन गई है कि रोजाना शाम होते ही दिल्ली मेट्रो की ट्रेनों में मच्छर काटना शुरू कर देते हैं। प्रगति मैदान, इंद्रप्रस्थ, यमुना बैंक, लक्ष्मी नगर, आनंद विहार सहित कई मेट्रो स्टेशनों पर रोजाना शाम 6 बजे के बाद से मच्छरों का प्रकोप शुरू हो जाता है। इसके चलते इन दिनों मेट्रो ट्रेन में मच्छरों के चलते यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उधर, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि इस बार मच्छरों का प्रकोप ज्यादा है। वहीं, उनका कहना है कि ये मच्छर डेंगू व मलेरिया वाले नहीं हैं। अभी फलेरिया फैलाने वाले मच्छर ज्यादा हैं।

उधर, दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी भी शहर में बढ़ते मच्छरों को लेकर दिल्ली नगर निगम में सत्तासीन भाजपा पर हमला करती रही है। आप नेता दुर्गेश पाठक के मुताबिक, दिल्ली है तो देश की राजधानी, लेकिन नगर निगम में भाजपा के शासन ने दिल्ली को मच्छरों की राजधानी बना दिया है। भाजपा 15 साल से नगर निगम पर शासन कर रही है। वहीं, आज दिल्ली में जगह-जगह गंदगी के अंबार हैं, जिसके कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं और फॉगिंग नहीं करवाई जा रही।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का सर्वे कहता है कि आज दिल्ली सबसे गंदी अवस्था में है, उसके कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं और दिल्ली में दवा का छिड़काव नहीं होने के कारण मच्छर मर नहीं रहे। दिल्ली का बुरा हाल हो चुका है। भाजपा ने दिल्ली को मच्छरों की राजधानी बना दिया है। एमसीडी को तुरंत शहर में फॉगिंग शुरू करनी चाहिए। अगर फॉगिंग शुरू नहीं की जाती तो दिल्ली कि जनता भाजपा के विरोध में सड़क पर उतरेगी।

अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के 12 सदस्यों को सुनाई उम्रकैद की सजा, दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को कहा कि जयपुर की एक अदालत ने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के राजस्थान 'मॉड्यूल' के 12 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिन्हें पुलिस बल के विशेष प्रकोष्ठ ने गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मार्च 2014 में, विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तानी नागरिक जिया-उर-रहमान उर्फ वकास को गिरफ्तार किया था. बयान में कहा गया है कि वकास अपने फरार साथियों के साथ देश भर में बम विस्फोटों के कई मामलों में वांछित था. वकास की गिरफ्तारी के बाद तीन और आतंकवादी मोहम्मद महरूफ , मोहम्मद वकार अजहर और शाकिब अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया था.

बयान में कहा गया है कि जयपुर और जोधपुर से पकड़े गए आतंकवादियों के पास से संदिग्ध विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व टाइमर आदि की बरामदगी की गई थी. आईएम के राजस्थान 'मॉड्यूल' के संस्थापक सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान एटीएस ने 10 और आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था. अदालत ने बुधवार को 13 आरोपियों में से एक को छोड़कर सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई.

मरहूम इंस्पेक्टर शर्मा के परिवार को दिए जाएं- बता दें कि बीते 15 मार्च को दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या और 2008 बाटला हाउस मुठभेड़ से जुड़े अन्य मामलों के दोषी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई थी. अदालत ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस करार देते हुए दोषी आरिज को फांसी की सजा सुनाई थी. अदालत ने आरिज खान पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. साथ ही अदालत ने निर्देश दिए थे कि 10 लाख रुपये तत्काल प्रभाव से मरहूम इंस्पेक्टर शर्मा के परिवार को दिए जाएं.

मृत्युदंड का विरोध किया था

पुलिस ने आतंकवादी संगठन 'इंडियन मुजाहिदीन' से कथित रूप से जुड़े खान को मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध किया था और कहा था कि यह केवल हत्या का मामला नहीं है, बल्कि न्याय की रक्षा करने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारी की हत्या का मामला है. जिसके बाद अदालत ने यह फैसला दिया था. पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक एटी अंसारी ने कहा कि इस मामले में ऐसी सजा दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे अन्य लोगों को भी सीख मिले और यह सजा मृत्युदंड होनी चाहिए.

संपादकीय

कुछ रह गए तो सब पर खतरा

एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया- क्या यह नारा याद है आपको। वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण का मूल सिद्धांत यह है कि जितनी जल्दी हो सके, ज्यादातर लोगों को वैक्सीन की सुरक्षा दे दी जाए, तभी महामारी की आफत से निजात पाई जा सकती है। कोविड-19 फैलाने वाले कोरोना वायरस के मामले में तो यह और भी जरूरी है। ऐसे वायरस की दिक्कत यह होती है कि वे अगर रहेंगे, तो नए रूप धरते रहेंगे और हमारी चुनौतियां बदलते, बढ़ाते रहेंगे। आप यह सोचते हुए राहत की आरामकुरसी पर इत्मीनान से बैठे होंगे कि मैंने तो वैक्सीन ले ली है, तभी हो सकता है कि वायरस ऐसा वेष धरकर आपका दरवाजा खटखटाए, जिसके लिए आपकी वैक्सीन भी तैयार न हो। इसलिए जरूरी है कि ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लगाई जाए और पूरी दुनिया में लगाई जाए। सुरक्षा का हमारे पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। दुनिया के देशों में सिर्फ इजरायल ही ऐसा है, जिसने अपने सभी नागरिकों को वैक्सीन की दोनों खुराक दे दी है। अमेरिका ने कहा है कि वह एक मई तक इस काम को अंजाम दे देगा। ब्रिटेन ने अगस्त को लक्ष्य बनाया है। पर हम भारतीयों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। संतोष की बात सिर्फ इतनी है कि यहां बहुत तेजी से टीकाकरण चल रहा है। समस्या यह जरूर है कि हमारे यहां जिस बड़ी तादाद में टीकाकरण की जरूरत है, उसके मुकाबले हमारा स्वास्थ्य-इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम है, इसलिए समय तो लगेगा ही। लेकिन दुनिया के बहुत से देशों की स्थिति तो शायद इतनी अच्छी भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरस की बात मानें, तो दुनिया के 130 देश ऐसे हैं, जहां अभी तक वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं पहुंची है। विश्व स्वास्थ्य संगठन बार-बार कह रहा है कि अगर यही स्थिति रही, तो यह महामारी हाल-फिलहाल में नहीं जाने वाली। यानी जो देश पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करके फिर से पुराने दिनों की रौनक में लौटने का रोडमैप बना रहे हैं, उनके सुरक्षित भविष्य की भी कोई गारंटी नहीं होगी। जिस वैक्सीन को रामबाण मानकर हमने पिछले 12 महीने जैसे-तैसे काटे थे, वह हासिल भले ही हो गई, पर अपने लक्ष्य से बहुत दूर है।

तो इस लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता क्या है? एक रास्ता वह है, जो पिछले साल अक्तूबर में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने सुझाया था। इन दोनों देशों ने विश्व व्यापार संगठन को एक पत्र लिखकर यह आग्रह किया था कि कोविड-19 की बनने वाली वैक्सीन से बौद्धिक संपदा अधिकार यानी पेटेंट वगैरह को हटा लिया जाए। इससे इस वैक्सीन को कोई भी कहीं भी बना सकेगा और कहीं भी भेज सकेगा। फिलहाल सबसे बड़ी जरूरत यही है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीन बने, सस्ती बने और सबको उपलब्ध हो और सघन टीकाकरण हो। जाहिर है, इन पत्रों पर किसी ने कान नहीं दिए। उसके बाद से अब तक दुनिया के 80 देश ऐसे पत्र लिख चुके हैं। अभी कोई इस पर ध्यान भले न दे रहा हो, लेकिन इसने अमेरिका की दवा कंपनियों को जरूर चिंतित कर दिया है। इन कंपनियों ने अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन को एक संयुक्त ज्ञापन भेजकर कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका ऐसी मांग कर रहे हैं और किसी भी तरह से ऐसा होने से रोका जाए। बाइडन ने इस पर चुप्पी साध ली है, वह न तो इन कंपनियों को नाराज करना चाहते हैं और न ही दुनिया के गुस्से का शिकार बनना चाहते हैं। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कंपनियों ने वैक्सीन का विकास और निर्माण अपने निवेश से नहीं किया है, इनमें से लगभग सभी की अमेरिकी सरकार ने बड़ी आर्थिक मदद की है। सबसे पहले वैक्सीन को बाजार में लाने वाली मॉडेरना को तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इसके लिए 50 करोड़ डॉलर की मदद की थी। यानी अमेरिकी कंपनियों की जितनी भी वैक्सीन बाजार में उतर चुकी हैं, उनमें उनका खुद का नहीं, बल्कि वहां के लोगों और कंपनियों द्वारा दिए गए कर का पैसा है। ये कर भी उन्होंने अपनी उस कमाई में से चुकाए हैं, जो पूरी दुनिया के लोगों के माइक्रोसॉफ्ट और एडोब के सॉफ्टवेयर खरीदने, गूगल और एंड्राएड के इस्तेमाल करने या अमेजन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खरीदारी से उन्हें हुई है। इस गणित से इन टीकों पर पूरी दुनिया का अधिकार बनता है। अब अमेरिकी सरकार के निवेश से इन दवा कंपनियों के शेयरों के भाव लगातार बुलंदी पर जा रहे हैं और उनका बाजार पूंजीकरण भी तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में एक खबर बांग्लादेश की छपी है। बांग्लादेश की एक दवा कंपनी है इन्सेप्टा, जो वैक्सीन भी बनाती है। उसने वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की तकरीबन सभी कंपनियों से कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए मदद मांगी है, लेकिन अभी तक किसी ने पलटकर जवाब तक नहीं दिया है। अमेरिकी कंपनियां खासतौर पर किसी अन्य देश की कंपनी के साथ समझौता करने से बच रही हैं। एकमात्र अपवाद जॉनसन ऐंड जॉनसन है, जिसने एक भारतीय कंपनी से वैक्सीन की एक करोड़ खुराक बनाने का समझौता किया है। जबकि ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका की कोवीशील्ड भारत की सीरम इंडिया में बन रही है और यहां इस्तेमाल भी हो रही है। इसी तरह, रूस ने भी अपनी स्पूतनिक वैक्सीन बनाने के लिए डॉ. रेड्डी लेबोरेटरीज से समझौता किया है। अगर बौद्धिक संपदा अधिकार पर भारत और दक्षिण अफ्रीका की मांग स्वीकार कर ली जाती है, तो भारतीय व तमाम दूसरे देशों की और कंपनियां आगे आ सकती हैं और पूरी दुनिया में वैक्सीन की किल्लत खत्म हो सकती है। अगर नहीं मानी जाती है, तो आगे जाकर यह भारत को परेशान भी कर सकती है। तब यह पूछा जाएगा कि भारत अपने यहां विकसित वैक्सीन को बौद्धिक संपदा अधिकार से क्यों नहीं मुक्त कर देता? जब बौद्धिक संपदा कानून को पूरी दुनिया में लागू करने के लिए विश्व व्यापार संगठन ने आस्तीनें चढ़ाई थीं, तब इसे मानव सभ्यता का एक बड़ा कदम कहा जा रहा था, लेकिन अब जब इस सभ्यता पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो यही कानून अड़चन बना हुआ है।

प्रवीण कुमार सिंह

श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार पैदा करने वाली नीतियों पर जोर देना जरूरी

केंद्र सरकार ने नया लेबर कोड यानी श्रम संहिता को लागू करने का मन बनाया है। इसमें यदि किसी श्रमिक को कदाचरण के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है तो 90 दिन के अंदर निर्णय करना अनिवार्य बना दिया गया है। इसी तरह एक वर्ष से अधिक अवधि तक काम करने वालों को ग्रेच्युटी मिलने के प्रविधान के साथ अल्पकालीन श्रमिकों को वे सभी सुविधाएं देना अनिवार्य कर दिया गया है, जो स्थायी श्रमिकों को मिलती हैं। यदि किसी कारखाने को बंद करना हो अथवा श्रमिकों की छंटनी करनी हो तो पहले सौ से अधिक श्रमिकों वाले उद्योगों को सरकार से अनुमति लेकर ऐसा करने का अधिकार था। अब यह सीमा बढ़ाकर तीन सौ श्रमिक कर दी गई है। इस पर कुछ श्रमिक संगठन आपत्ति जता रहे हैं। लेबर कोड लागू करने के पीछे यह सोच है कि इससे मैन्यूफैक्चरिंग में बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे।

हमारे श्रम बाजार में बड़ी संख्या में युवा प्रवेश कर रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के बाद छोटे उद्योगों और उनमें कार्यरत श्रमिकों की हालत खराब हुई है। जहां पहले पांच आदमी सब्जी बेचते थे, आज वहां कहीं अधिक आदमी सब्जी बेचते देखे जा सकते हैं। इस कारण सब्जी बेचने वालों की दैनिक आय कम हो गई है, क्योंकि सब्जी बेचने वालों की संख्या बढ़ गई है। बेरोजगार हुए श्रमिक इस प्रकार के धंधे करने को मजबूर हैं। उद्योगों में श्रमिकों की खपत नहीं बढ़ रही है। मेरी जानकारी में एक चीनी मिल है, जो एक समय दो हजार टन गन्ना प्रतिदिन पेराई करती थी और उसमें दो हजार श्रमिक कार्यरत थे। आज उसी मिल में आठ हजार टन गन्ने की प्रतिदिन पेराई होती है, लेकिन कुल श्रमिकों की संख्या मात्र पांच सौ रह गई है। इसका कारण है मशीनीकरण। मशीन की तुलना में

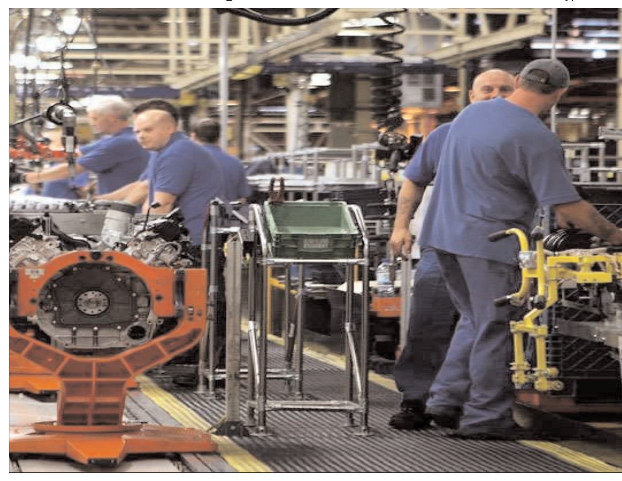

श्रमिक का मूल्य उद्यमी को अधिक पड़ता है। चूंकि उद्यमी उत्पादन लागत को न्यून रखना चाहता है, इसलिए वह ऑटोमेटिक मशीनों का उपयोग करता है।

उद्यमियों को श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रेरित करने के लिए जरूरी है कि मशीनों की तुलना में श्रम से उत्पादन करना सस्ता पड़े। यदि एक श्रमिक पूर्व में एक दिन में 10 मीटर कपड़ा बुनता था तो उद्यमी चाहेगा कि वह अब 20 मीटर कपड़ा बुनने लगे। यदि श्रमिक की उत्पादकता बढ़ती है तो उद्यमी के लिए श्रमिक से कपड़े की बुनाई करना ज्यादा लाभप्रद होगा। वह मशीन से उत्पादन नहीं करना चाहेगा, लेकिन श्रम की उत्पादकता बढ़ने के साथ-साथ श्रमिकों के रोजगार कम हो जाते हैं। जैसे 20 मीटर कपड़े की बुनाई करने में यदि पहले दो श्रमिकों की जरूरत होती थी तो उत्पादकता बढ़ने के बाद उसी 20 मीटर कपड़े की बुनाई करने में अब केवल एक श्रमिक की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार हमारे एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं।

भारत में चीन का मॉडल लागू नहीं होता। चीन ने यह किया कि जो श्रमिक पहले 10 मीटर बुनाई करता था, उसे प्रेरित किया कि वह 20 मीटर बुनाई करे। इसके साथ उसने कपड़े के बाजार का तीव्र विस्तार किया। पहले यदि बाजार में 10 मीटर कपड़े की मांग थी तो अब 40 मीटर कपड़े की मांग पैदा की। इस प्रकार जो उद्यमी पहले 10 मीटर कपड़े का उत्पादन करने में एक श्रमिक का उपयोग करता था, वह समय क्रम में 40 मीटर कपड़े का उत्पादन करने में दो श्रमिकों का उपयोग करने लगा। चीन में तीव्र आर्थिक विकास होने के कारण उत्पादन बढ़ा, रोजगार बढ़े, श्रम की मांग बढ़ी और वेतन भी बढ़े, लेकिन हमारी परिस्थिति में यह मॉडल लागू नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी आर्थिक विकास दर चीन के मुकाबले कम है और पिछले कुछ वर्षों में गिरती जा रही है। हमारे बाजार का विस्तार इतनी तीव्र गति से नहीं हो रहा है कि उत्पादकता बढ़ने के साथ-साथ रोजगार भी बढ़ें। इस परिस्थिति में श्रम की उत्पादकता बढ़ाना हमारे लिए अनिवार्य है। यदि हम अपने श्रमिकों की उत्पादकता नहीं बढ़ाते और महंगा उत्पादन करते रहते हैं तो हम विश्व बाजार से बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमें हर हाल में श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाना होगा, जिससे रोजगार के अवसर चाहे कम बनें, लेकिन वे बनें तो रहें। इस दृष्टि से श्रम संहिता का प्रमुख उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने को प्रोत्साहन देना होना चाहिए।

आज उद्योगों के लिए श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने में प्रमुख व्यवधान यह है कि उद्यमी बिना कोई कारण बताए अकुशल श्रमिक को हटा नहीं सकता। चूंकि लेबर कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया पेचीदा हो जाती है, इसलिए उद्यमी श्रमिक से अधिक काम लेने में असफल रहता है। डेवलपिंग इकोनॉमी पत्रिका में छपे एक पत्र के अनुसार 1978 में भारत के श्रमिकों की उत्पादकता चीन की तुलना में 47 प्रतिशत अधिक थी, जो 2004 में चीन की तुलना में 42 प्रतिशत कम हो गई। हमारे सामने विश्व बाजार में टिकने के लिए जरूरी है कि हम अपने श्रम की उत्पादकता बढाएं। इसमें लेबर कोड प्रभावी नहीं, क्योंकि बिना कारण बताए श्रमिकों को हटाने का अधिकार नहीं दिया गया है। यदि श्रमिकों की उत्पादकता नहीं बढ़ती तो हम विश्व बाजार में पिछड़ते जाएंगे।

मध्यम उद्योगों को बंद करने अथवा छंटनी करने के अधिकार देने से श्रम की उत्पादकता नहीं बढ़ती। यदि हम श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ा लें और विश्व बाजार में टिके रहें तो रोजगार घटेंगे, क्योंकि उतने ही माल का उत्पादन करने में कम संख्या में श्रमिकों की जरूरत होगी। इसलिए जरूरत इसकी है कि सरकार रोजगार सृजित करने की दूसरी नीतियों पर अमल करे।

इसमें एक संभावना है कि उन मशीनों पर अधिक दर से टैक्स वसूल किया जाए, जिनसे श्रम का विस्थापन होता है, जैसे जेसीबी अथवा हार्वेस्टर। दूसरी संभावना है कि सरकारी ठेकों में व्यवस्था बना दी जाए कि अमुक कार्य मशीनों के स्थान पर श्रमिकों के माध्यम से होगा। तीसरी संभावना है कि जिस माल के उत्पादन पर श्रम का उपयोग अधिक हुआ है, उस पर जीएसटी अथवा आयकर कम दर से वसूल किया जाए। अन्य तरीके भी हो सकते हैं। मूल बात यह है कि हमारे सामने कठिन चुनौती है। एक तरफ विश्व बाजार में टिके रहने के लिए श्रम की उत्पादकता बढ़ाना जरूरी है, जिसके कारण रोजगार के अवसर कम बनेंगे। दूसरी तरफ हमारे लिए रोजगार सृजित करना भी आवश्यक है। बीच का कोई रास्ता रोजगारपरक नीतियों को लागू करके ही निकाला जा सकता है। इस रास्ते की तलाश की जानी चाहिए।

इसमें एक संभावना है कि उन मशीनों पर अधिक दर से टैक्स वसूल किया जाए, जिनसे श्रम का विस्थापन होता है, जैसे जेसीबी अथवा हार्वेस्टर। दूसरी संभावना है कि सरकारी ठेकों में व्यवस्था बना दी जाए कि अमुक कार्य मशीनों के स्थान पर श्रमिकों के माध्यम से होगा। तीसरी संभावना है कि जिस माल के उत्पादन पर श्रम का उपयोग अधिक हुआ है, उस पर जीएसटी अथवा आयकर कम दर से वसूल किया जाए। अन्य तरीके भी हो सकते हैं। मूल बात यह है कि हमारे सामने कठिन चुनौती है। एक तरफ विश्व बाजार में टिके रहने के लिए श्रम की उत्पादकता बढ़ाना जरूरी है, जिसके कारण रोजगार के अवसर कम बनेंगे।

कुशल प्रबंधन के माध्यम से बैंकों के निजीकरण का सराहनीय प्रयास

बैंकिंग व्यवसाय के निजीकरण की प्रक्रिया पिछले कुछ वर्षो से तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 1970 के पहले यह व्यवसाय निजी हाथों में था। देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के अपने अपने बैंक थे। वर्ष 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके पीछे तर्क था कि ये बैंक अमीरों के लिए हैं, गरीबों, किसानों, मजदूरों की पहुंच के बाहर हैं। न उनके खाते इन बैंकों में हैं, न उनको लोन मिलता है। इनकी जमाराशि का बड़ा हिस्सा उद्योगपति अपने व्यवसाय में लगाते हैं, विकास की योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज कल्याण के लिए धन उपलब्ध नहीं कराया जाता। समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की पूर्ति के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा गया। भारत की अर्थव्यवस्था उन दिनों बहुत कमजोर थी। वर्ष 1980 में छह और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों का विस्तार हुआ, बड़ी संख्या में नई शाखाएं गांवों और छोटे शहरों में भी खोली गईं, ऋण की सुविधा किसानों और गरीबों के लिए खोल दी गई, यद्यपि उन्हें इसका उतना लाभ वर्षो नहीं मिला, जो अपेक्षित था। साहूकारों का शोषण जारी रहा, बैंक में गरीबों के खातों की संख्या बहुत कम रही। लेकिन पिछले लगभग तीन दशकों में भारत में बैंकिंग कारोबार में व्यापक तेजी आई है। साथ ही यह भी देखने में आया है कि सरकारी बैंकों में होने वाले घाटे की पूर्ति सरकारी अनुदान से की जाती है जिसका बोझ आम आदमी पर पड़ता है। सार्वजनिक बैंकों का कुल अदेय ऋण यानी एनपीए वर्ष 2020 में 6.8 अरब था, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है।

सार्वजनिक बैंकों के एनपीए की समस्या पिछले कई दशकों से है जो सरकारी दबाव, भ्रष्टाचार एवं कुप्रबंध के कारण बढ़ता गया। इतनी बड़ी रकम यदि विकास परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हो पाती तो अर्थव्यवस्था को कितना लाभ हो सकता था। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने 2016 में सार्वजनिक बैंकों के बैलेंसशीट के क्लीनिंग की बात कही थी। उनका मानना था कि ये बैंक उद्योगों और बुनियादी ढांचों के लिए धन उपलब्ध कराने की अपेक्षा पूरी नहीं कर रहे हैं। अक्टूबर 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक बैंकों के रीकैपिटलाइजेशन के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी। यह रकम बांड, बजट और इन कंपनियों के शेयरों की बिक्री से जुटाई जानी थी। किसानों को सार्वजनिक बैंकों ने जो ऋण दिए हैं उनका अदेय लगभग 15.85 प्रतिशत है जिसकी भरपाई के लिए 70 हजार करोड़ रुपये के कार्पस तीन वर्षो के लिए बनाए जाने की बात कही जा रही है। इसके पूर्व भी कई बार इन बैंकों को सरकारी मदद दी गई थी जिसके अभाव में कुछ बैंक तो दिवालिया हो गए होते। सरकारी बैंकों में मात्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है जिसकी प्रबंध व्यवस्था विवादों के घेरे में नहीं रही। पिछले कुछ वर्षो से बैंकिंग व्यवसाय में सार्वजनिक बैंकों का हिस्सा घटता जा रहा है और निजी क्षेत्र के बैंकों का बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2010 में 75.1 प्रतिशत ऋण सरकारी बैंकों ने दिया जो 2020 में घटकर 57.3 प्रतिशत हो गया। इस बीच निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया गया ऋण 17.4 से बढ़कर 35 प्रतिशत पर आ गया। बैंकों में डिपॉजिट की स्थिति भी यही रही। मार्च 2012 में सार्वजनिक बैंकों में 74.76 प्रतिशत डिपॉजिट था जो सितंबर 2020 में घटकर 62.1 प्रतिशत रह गया। इस बीच निजी क्षेत्र के बैंकों में डिपॉजिट 17.8 से बढ़कर 29 प्रतिशत हो गया। सार्वजनिक बैंकों की प्रबंध व्यवस्था और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने 12 बैंकों को मिलाकर चार बड़े बैंकों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया था। पंजाब नेशनल बैंक के साथ बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक के साथ इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक के साथ केनरा बैंक एवं आंध्र बैंक के साथ यूनियन बैंक के विलय की मंजूरी दी गई।

रिजर्व बैंक की एक आंतरिक समिति ने यह सुझाव दिया है कि बड़ी कंपनियां और औद्योगिक घरानों को निजी बैंक खोलने के लाइसेंस दिए जाएं जिससे बैंकिंग व्यवसाय में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश हो और इस क्षेत्र को उनकी प्रबंध क्षमता और कुशलता का लाभ मिले। इस बीच 2021-22 का बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने दो सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण की घोषणा कर दी जिससे बैंकिंग क्षेत्र में भूचाल आ गया। इसी माह बैंक कर्मचारी यूनियनों ने हड़ताल किया। सरकार ने इस निजीकरण से 1.75 लाख करोड़ रुपये के विनियोग का लक्ष्य रखा है। सरकार के इस निर्णय से स्पष्ट है कि बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया देश में शुरू हो चुकी है जो अर्थव्यवस्था को गति देगी। अधिकांश विकसित देशों में बैंकों का आकार हमारे सार्वजनिक बैंकों से कई गुना ज्यादा है, उनके डिपॉजिट, ऋण देने की क्षमता, विभिन्न सेवाएं और बुनियादी ढांचा कहीं अधिक और उन्नत है। देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर के बैंकों की आवश्यकता है जो निजी क्षेत्र ही दे सकता है। देश के निजी क्षेत्र के बड़े बैंकों आइसीआइसीआइ, एचडीएफसी, एक्सिस आदि का व्यापार पिछले कुछ वर्षो में उनकी कार्यक्षमता, कुशल प्रबंधन एवं ग्राहक सेवाओं के कारण तेजी से बढ़ा है जो निजी क्षेत्र में बढ़ते विश्वास का द्योतक है। जहां तक बैंकों में डिपॉजिट की सुरक्षा का प्रश्न है, निजी क्षेत्र के बैंक भी उन्हीं नियमों से अनुशासित हैं जिनसे सार्वजनिक बैंक, देश के सभी बैंक रिजर्व बैंक के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

कट्टी के बाद फिर दोस्ती

भारत-पाक रिश्तों के मोर्चे पर इधर कुछ समय से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा कि पाकिस्तान के लोग भी दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग का संबंध देखना चाहते हैं। इसके ठीक बाद खबर आई कि पाकिस्तान ने भारत से कॉटन और यार्न के आयात पर लगी रोक हटाने का फैसला कर लिया है। इससे पहले पाकिस्तान के गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाक पीएम इमरान खान को पत्र भेजकर बधाई दी थी। इसी पत्र का जवाब इमरान खान ने दिया है। इससे पहले दोनों देशों की सेना में युद्धविराम समझौते का पालन करने पर सहमति बनी और फिर पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने कहा कि दोनों देशों को पुरानी बातें पीछे छोड़कर शांति और सहयोग की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इन सबसे सकारात्मक माहौल बना जिसने व्यापार शुरू होने की राह आसान की। हालांकि अभी इस मामले में कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं, लेकिन दोनों पक्षों से मिल रहे सकारात्मक संकेतों को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि इसमें और अड़चन नहीं आएगी।

वैसे देखा जाए तो तमाम उतार-चढ़ावों के बावजूद 2014 में एनडीए शासन शुरू होने के बाद काफी समय तक दोनों देशों के रिश्तों में उत्साह बना रहा। प्रधानमंत्री मोदी का नवाज शरीफ के परिवार में हो रही शादी के मौके पर औपचारिक निमंत्रण के बगैर पहुंच जाना रिश्तों की गर्मजोशी का ऐसा सबूत है जो कूटनीतिक हलकों में याद रखे जाने लायक माना गया। यहां तक कि जनवरी 2016 में हुए पठानकोट आतंकी हमले के बाद भी दोनों सरकारों के बीच यह समझ बनी रही कि कुछ नॉन स्टेट ऐक्टर हैं जिनकी कोशिश हर कीमत पर भारत-पाक रिश्तों को बिगाड़ने की है। इनसे मुकाबले के लिए दोनों सरकारों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान से जांच के लिए आई टीम को पठानकोट एयरबेस में जाकर गवाहों और चश्मदीदों से पूछताछ करने दिया गया। मगर उसी साल सितंबर में हुए उड़ी हमले के बाद हालात बदल गए। फिर रही-सही कसर पुलवामा हमले ने पूरी कर दी।

बहरहाल, एक साझा संस्कृति से जुड़े हुए दोनों परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों के पास बातचीत से मसले सुलझाने और शांति-सहयोग के रिश्ते कायम करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए युद्ध में उतरने की हद तक जाने के बाद भी भारत और पाकिस्तान फिर-फिर वार्ता की मेज पर वापस लौटते रहे हैं। यह क्रम इतनी बार दोहराया जा चुका है कि किसी भी पक्ष की छोटी से छोटी हरकत भी जानी-पहचानी लगने लगी है। इसमें कुछ खास हो सकता है तो यही कि इस बार सिर्फ दोस्ती करने की नहीं बल्कि उसे टिकाने की भी तरकीब ढूंढी जाए। उम्मीद करें कि दोनों देशों का नेतृत्व 2021 में कुछ ऐसी जुगत निकालेगा कि रिश्ते न सिर्फ क्रिकेट और कारोबार से आगे जाएं बल्कि इतने पारदर्शी हों कि किसी की चालबाजी से चकनाचूर न हों।

ममता का अहंकार और मोदी विरोध कहीं न पड़ जाए भारी

वैसे तो चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों में जबरदस्त जोर-आजमाइश चल रही है, लेकिन राजनीतिक पंडितों से लेकर आमजन तक के अंदर सबसे ज्यादा दिलचस्पी बंगाल को लेकर है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल विधानसभा का चुनाव काफी अहम है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत पार्टी के तमाम राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नेता मैदान में जिस तरह से पसीना बहा रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस चुनाव को जीतना पार्टी के लिए कितना मायने रखता है। उसके सामने दो बार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो तीसरी बार राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही हैं। राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहीं मुख्यमंत्री बंगाली अस्मिता के नाम पर वोट मांग रही हैं और बार-बार भाजपा को बाहरी बताकर खारिज कर रही हैं।

बकौल ममता बनर्जी भाजपा के नेता उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें बंगाल और बंगाली समाज की कोई समझ ही नहीं है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि बंगाली अपनी संस्कृति, पहचान, भाषा, खान-पान और रहन-सहन पर काफी गर्व करते हैं। इसके पीछे ठोस कारण भी हैं। उनके पास रवींद्रनाथ टैगोर से लेकर सत्यजित रे तक गर्व करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ख्यात स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले ने जब कहा था कि बंगाल जो आज सोचता है, वह भारत कल सोचता है, उसके बाद से गंगा नदी में काफी पानी बह चुका है। उनका यह गर्व खोखले दर्प के अलावा कुछ नहीं है।

भाजपा के विरोध के नाम पर ममता बनर्जी किसी हद तक जाने को तैयार हैं। कभी उनके दाहिने हाथ रहे और अब नंदीग्राम से भाजपा के उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी और उनके साथ तृणमूल छोड़ने वाले नेताओं को वे मीरजाफर की संज्ञा दे रही हैं। उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि मीरजाफर ने 1757 में प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाज सिराजुद्दौला को धोखा देकर जिस ब्रिटिश सेना और उसके सेनापति राबर्ट क्लाइव का साथ दिया था, वे विजयी रहे थे। सिर्फ विरोध के नाम पर भाजपा का विरोध करने के फेर में ममता खुद अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही हैं।बंगालियों के इस अहंकार का प्रत्यक्ष अनुभव इस लेखक को भी है। बचपन से लेकर लगभग तीन दशक तक बंगाल में रहने के दौरान हुए अनुभवों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि बंगाली अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं। उन्हें प्रेमचंद, प्रसाद, पंत या निराला के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। वे अपने कवियों और लेखकों के अलावा किसी को तवज्जो नहीं देते हैं। रसगुल्ले के आगे सभी मिठाइयां बेकार हैं। बंगालियों की तरह कोई फुटबॉल नहीं खेल सकता है। यहां तक कि जब वे देश से बाहर जाते हैं तो खुद को भारतीय के बजाय बंगाली कहलाना पसंद करते हैं और बंगाल में रहने वाले गैर-बंगालियों को वे हिंदुस्तानी कहते हैं। इसी का नतीजा है कि बंगाल धीरे-धीरे समस्याओं के अंबार तले दबता गया, लेकिन बंगाल के राजनेता इससे ध्यान हटाने के लिए अपनी संस्कृति को ढाल बनाते रहे। वाम मोर्चा के लगभग साढ़े तीन दशक के शासनकाल के बाद पिछले दस साल में ममता बनर्जी ने भी यही किया है।

जब बात बंगाल और बंगालियों की आती है तो सारे राजनीतिक विरोध धरे के धरे रह जाते हैं। पाठकों को याद होगा कि कैसे 2005 में जब सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर बिठा दिया गया था तो लोकसभा अध्यक्ष और मार्क्?सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता सोमनाथ चटर्जी से लेकर रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी और बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने विरोध जताया था और लोकसभा में काफी हंगामा भी हुआ था। क्रिकेट को औपनिवेशिक खेल और गुलामी का प्रतीक बताने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का इस तरह से गांगुली के समर्थन में आना काफी चौंकाने वाला था, लेकिन यही बंगाल की हकीकत है।

बंगाल के लोगों और उनके बुद्धिजीवियों को समझना होगा कि बीते जमाने की उपलब्धियों का कोई अर्थ नहीं है। बंगाल के महान इतिहास से किसी को इन्कार नहीं है, लेकिन भविष्य को संवारने के लिए वर्तमान को सहेजना होगा। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि राज्य को फिर से औद्योगिक विकास के रास्ते पर लाया जाए। कभी औद्योगिक उत्पादन में सबसे आगे रहे इस राज्य में कल-कारखाने बंद हो चुके हैं। राज्य के पढ़े-लिखे नौजवान और समर्थ पूंजीपति दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य की स्थिति काफी नाजुक है। कोरोना की महामारी ने इसे उजागर किया है। देश में सबसे कम टेस्टिंग और सबसे ज्यादा मृत्यु दर पश्चिम बंगाल में ही दर्ज की गई। बंगाल को फिर से उसका गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिए राज्य के बुद्धिजीवियों को इतिहासजीवी होने से बचना होगा। बंगाल के पास बौद्धिक और प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका दोहन करने के लिए जिस राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है, वह ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के पास नहीं है। वे भले ही बहुत ईमानदार हैं, लेकिन अपने भतीजे के भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा पाना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यह कमी उन्हें बहुत भारी पड़ सकती है। लिहाजा चुनाव नतीजों का सभी का बेसब्री से इंतजार रहेगा।

बंगाल के लोगों और उनके बुद्धिजीवियों को समझना होगा कि बीते जमाने की उपलब्धियों का कोई अर्थ नहीं है। बंगाल के महान इतिहास से किसी को इन्कार नहीं है, लेकिन भविष्य को संवारने के लिए वर्तमान को सहेजना होगा। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि राज्य को फिर से औद्योगिक विकास के रास्ते पर लाया जाए। कभी औद्योगिक उत्पादन में सबसे आगे रहे इस राज्य में कल-कारखाने बंद हो चुके हैं। राज्य के पढ़े-लिखे नौजवान और समर्थ पूंजीपति दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य की स्थिति काफी नाजुक है। कोरोना की महामारी ने इसे उजागर किया है। देश में सबसे कम टेस्टिंग और सबसे ज्यादा मृत्यु दर पश्चिम बंगाल में ही दर्ज की गई।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

कोरोना वायरस संक्रमण पर यूपी में कक्षा आठ तक के निजी तथा सरकारी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद

लखनऊ । वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से गति पकड़ चुका है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी गंभीरता को देखते हुए कक्षा आठ तक के सभी सरकारी तथा निजी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश जारी कर दिया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर कोर टीम (टीम-11) के साथ कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के साथ मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी तथा डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी भी अन्य अधिकारियों के साथ मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि इस दौरान शिक्षकों का स्कूलों में आना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में अधिकारी तय करें कि कक्षा नौ से 12 तक की शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के स्कूल में आगमन के दौरान स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने में जरा भी संकोच न करें।

होली के पर्व के अवकाश के बाद प्रदेश सरकार ने कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों में चार अप्रैल तक अवकाश घोषित किया था। अब इस अवधि को 11 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के फिर से बढ़ते मामलों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर समीक्षा बैठक में कहा कि कोरोना वायरस के हर संदिग्ध मामलों में आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि समूहों में संचालित संस्थानों, बालिका संरक्षण गृह, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, आदि में टेस्टिंग प्राथमिकता पर की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समितियों को भी पूरी तरह से सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। संक्रमण की निगरानी के लिए सीएम ने हर वार्ड और गांव में निगरानी समिति के गठन के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के संबंध में लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। सार्वजनिक कार्यक्रमों में फिजिजल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जाए और हर जगह पर मास्क के अनिवार्य उपयोग पर विशेष ध्यान देना अनिवार्य हो।

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में रहस्यमय विस्फोट, एक की मौत- एक गंभीर

सिद्धार्थनगर । गुरुवार की देर रात सिद्धार्थनगर के नादेपार चौराहे पर स्थित किराने की दुकान में जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास मौजूद घरों की दीवारें हिल गई। घटना में मौके पर एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों के सहयोग से उसे इलाज के लिए संयुक्त जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी होने पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। विस्फोट को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। फिलहाल पुलिस घटना की असली वजह नहीं बता पा रही है।

यह है मामला- 30 वर्षीय राजमन नादेपार चौराहे पर किराने की दुकान चलाता था। देर रात वह अपने साथ विरेन्द्र गुप्ता कबाड़ी के साथ दुकान के अंदर मौजूद था। इसी बीच तेज आवाज के साथ जोरदार धमाका हुआ। राजमन की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि कबाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गया।

विस्फोट कितना जोरदार था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुकान में लगा शटर 15 फीट दूर जा गिरा। दुकान की दीवाल टूट कर गिर गई। आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को लगा जैसे भूकंप आ गया है। एसओ जोगिया का कहना है कि विस्फोट के कारण का पता नहीं चल सका है। जांच की जा रही है। मौके पर वह मामले की जांच में जुटे हुए हैं।

एसपी ने बताया- घटना के संबंध में सिद्धार्थनगर के पुलिस अधीक्षक राम अभिलाष त्रिपाठी ने कहा कि घटना के असली कारणों की जांच की जा रही है। जल्द ही सही जानकारी उपलब्ध होगी, इसके पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी।

संक्षिप्त खबर

बिहार में थानेदार ने काटा ई स्कूटी का चालान तो डीटीओ ऑफिस ने कहा- कैसे लें जुर्माना जब प्रावधान ही नहीं

बिहारशरीफ । ई स्कूटी सवार को बिना हेलमेट पकड़े जाने पर चालान काटना बिहारशरीफ जिले के सोहसराय थानाध्यक्ष को महंगा पड़ सकता है। पीड़ित थरथरी थाना क्षेत्र के खरजम्मा निवासी केशव कुमार ने वकील के माध्यम से थानाध्यक्ष को नोटिस भेजा है। नोटिस में उसने उल्लेख किया है कि 22 मार्च को वह बिहारशरीफ से घर लौट रहा था। उसी दौरान सोहसराय थाना क्षेत्र के किसान कॉलेज व 17 नंबर के बीच पुलिस ने उसकी ई स्कूटी रोक कर कागजात व हेलमेट की मांग की। जब युवक ने बताया कि ई स्कूटी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या हेलमेट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी अधिकतम स्पीड 25 किमी प्रति घंटा है। इसके बावजूद पुलिस ने उनके वाहन का चालान काट दिया।

केशव का कहना है कि उन्होंने पुलिस को कंपनी का दिया गया कार्ड भी दिखाया, जिस पर स्पष्ट लिखा था कि इसकी स्पीड 25 किमी प्रति घंटे से कम है। इस वाहन को मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, बिना लाइसेंस व बिना पंजीकरण के चलाया जा सकता है। हेलमेट पहनना ऐच्छिक है, इसकी बाध्यता नहीं है। बावजूद इसके पुलिस ने लाल चालान काट दिया और स्कूटी को जब्त कर पुलिस थाने ले गई। इसके बाद जब युवक 28 मार्च को थानाध्यक्ष श्याम किशोर सिंह से मिला तो उन्होंने एक हजार का चालान काट दिया और स्कूटी छोड़ दी। इससे पहले थानाध्यक्ष ने लाल चालान के आधार पर डीटीओ ऑफिस में बिना हेलमेट मामले में एक हजार रुपए फाइन जमा कराकर पावती लाकर देने को कहा था। जब युवक डीटीओ कार्यालय पहुंचा तो वहां कार्यालय के कर्मी ने कहा कि जब प्रावधान ही नहीं है तो हम फाइन किसका काटें। थक-हारकर युवक थानाध्यक्ष के पास दोबारा पहुंचा तो उन्होंने खुद चालान काट दिया और एक हजार रुपए जमा लेकर स्कूटी छोड़ दी।

इधर, नियम विरुद्ध तरीके से चालान काटने व नाहक छह दिनों तक ई स्कूटी जब्त रखने के मामले में युवक ने कोर्ट की शरण ले ली। कहा कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस है। ई स्कूटी पर हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है। फिर भी उस पर जुर्माना कर दिया गया। गुरुवार को अधिवक्ता सुनील कुमार पांडेय के माध्यम से सोहसराय थानाध्यक्ष को वकालतन नोटिस भेजी गई है। एक-दो दिन में युवक लोक शिकायत निवारण कोषांग में भी शिकायत दर्ज कराएगा। इधर, थानाध्यक्ष ने कहा कि डीटीओ ने लिखित आदेश दिया था कि ऐसे वाहन का भी चालान काटना है।

कोरोना से पंजाब में 60 और लोगों की मौत, टीकाकरण में आया 62 फीसदी से अधिक का उछाल

जालंधर/चंडीगढ़ । पंजाब में कोरोना वायरस का कहर और बढ़ गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमित 60 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 3187 लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में टीकाकरण में भी तेजी आ गई है। इसमें एक ही दिन में 62.93 फीसद का उछाल आया है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण के तहत 45 साल के पार सभी लोगों को टीका लगाए जाने को लेकर पंजाब में लोगों का रुझान सकारात्मक रहा। वीरवार को पंजाब में कुल 73954 लोगों का टीकाकरण हुआ। यह आंकड़ा बुधवार को 45388 था। एक ही दिन में टीकाकरण में 62.93 फीसद का उछाल आया है। राज्य में वीरवार शाम तक कुल 810535 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इनमें 359506 हेल्थ केयर व फ्रंट लाइन वर्कर और 451029 अन्य लोग शामिल हैं।

पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामले और मौतें चिंता का विषय बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 60 लोगों की मौत हो गई तो इस साल एक ही दिन में संक्रमण के सर्वाधिक 3187 नए मामले सामने आए। 2291 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। जालंधर में सबसे ज्यादा 416, मोहाली में 409, लुधियाना में 376, अमृतसर में 332, पटियाला से 268, होशियारपुर 258, रोपड़ में 186, बठिंडा में 165, गुरदासपुर में 127 और कपूरथला में 100 लोगों की रिपोर्ट पाजिटिव आई। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 24644 हो गई है। इनमें से 334 मरीजों को आक्सीजन और 33 गंभीर मरीजों को वेंटीलेटर सपोर्ट पर रखा गया है।

राज्य में कोरोना के कारण मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 6926 हो गया है। 24 घंटे के दौरान अमृतसर में सबसे ज्यादा 11, जालंधर व होशियारपुर में नौ-नौ, लुधियाना में आठ, नवांशहर व मोहाली में चार-चार, गुरदासपुर में तीन, फिरोजपुर, पटियाला व संगरूर में दो-दो और बरनाला, बठिंडा, कपूरथला व पठानकोट में एक-एक कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया।

बिहार के डीजीपी पर है सवा करोड़ रुपये का कर्ज, एडीजी मुख्यालय के पास केवल 500 रुपए ही कैश

पटना । डीजीपी एसके सिंघल समेत बिहार कैडर के 154 आइपीएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक कर दिया है। सभी अफसरों को 31 मार्च तक ऑनलाइन जानकारी साझा करने की समय-सीमा दी गई थी। अधिसंख्य आइपीएस अफसरों ने बहुत नगण्य कैश होने की जानकारी दी है। हां, बैंक खातों में जरूर रुपये हैं। डीजीपी समेत अधिसंख्य पुलिस अफसरों ने कर्ज लेकर मकान और कार का शौक पूरा किया है। इसके अलावा हथियारों का शौक भी आइपीएस अफसरों को खूब है। एडीजी मुख्यालय जीतेंद्र कुमार के पास मात्र पांच सौ रुपये नकद हैं। पति-पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से हरिद्वारा में एक भू-खंड और नोयडा में एक फ्लैट है। इसके लिए इन्होंने होम लोन लिया है।

डीजीपी के पास नकद राशि नहीं है, मगर बैंक में 18 लाख रुपये जमा हैं। खात बात यह है कि डीजीपी ने फ्लैट खरीदने और बेटे की मेडिकल की पढ़ाई के लिए 1.36 करोड़ का कर्ज ले रखा है। डीजीपी डबल बैरल गन भी रखते हैं और नोएडा व गुरुग्राम में फ्लैट व जमीन भी है। डीजी आलोक राज के नाम पर 55 लाख और पत्नी के नाम पर 26 लाख रुपये का बांड है। उनके पास .32 बोर की राइफल है। पुरानी डीजल से चलने वाली एम्बेस्डर कार है, तो शास्त्री नगर में लगभग दो हजार वर्ग फीट का फ्लैट भी है। होमगार्ड और फायर सर्विस की डीजी शोभा ओहटकर और बिहार सशस्त्र पुलिस के डीजी आरएस भट्टी ने भी बैंक लोन ले रखा है। शोभा ओहटकर के पास 2.29 लाख नकद है। 20 लाख के म्युचअल फंड हैं। पुणे में एक घर के अलावा पटना में एक फ्लैट है, जिसके लिए 35 लाख का होमलोन लिया गया है। एक स्विफ्ट कार भी है। डीजी आरएस भट्टी के पास चंडीगढ़ में 1.80 करोड़ और अमृतसर में 88 लाख की पुश्तैनी जमीन है, जिसमें कई लोगों की हिस्सेदारी है। उनके पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है, मगर उनकी पत्नी के पास डेढ़ किलो सोने और दो किलो चांदी के आभूषण हैं।

अस्पताल संचालिका डॉ अलका राय पर बाराबंकी में एफआईआर

बाराबंकी । पंजाब में कुख्यात मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी के दौरान चर्चा में आई यूपी के बाराबंकी के नम्बर की एम्बुलेंस के रहस्यों से प्रशासन ने पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। गुरुवार देर रात सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पंकज सिंह ने अस्पताल की संचालिका डॉ अलका राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें उन्होंने बताया है कि 21 दिसंबर 2013 को इसका पंजीकरण डॉ अलका राय निवासी 56, रफीनगर के पते पर तत्कालीन पंजीयन अधिकारी ने किया था। इसका संचालन श्याम संजीवनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जीटी मऊ 2/5101 से किए जाने का प्रपत्र भी प्रस्तुत किया गया था।

एक अप्रैल को एम्बुलेंस का संचालन बिना फिटनेस वैधता और इंश्योरेन्स के किए जाने की जानकारी मिली। उन्होंने इस संबंध में एक अप्रैल को एसडीएम नवाबगंज का पत्र मिलने की बात कही है, जिसमें पंजीयन के वक्त प्रस्तुत निर्वाचन कार्ड फर्जी और जालसाजी कर बनाए जाने की आशंका जताई गई है। अंकित पते के स्थलीय सत्यापन में रफीनगर मरण 56 नम्बर का कोई मकान ही नहीं मिला, जबकि अभयनगर में इस नम्बर के मकान में एक परिवार के वर्षो से रहने की पुष्टि हुई। क्षेत्रीय सभासद और अन्य स्थानीय लोगों ने भी अस्पताल या डॉ अलका राय के यहां निवास करने की पुष्टि अपने बयान में नहीं की है।

नोटिस देकर भूल गया विभाग - पंजाब की रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट में मुख्तार अंसारी को जिस एंबुलेंस से लाया गया वह बाराबंकी सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ) में पंजीकृत है। चर्चा में बनी यूपी 41 एटी 7171 एंबुलेंस का 21 दिसंबर 2013 को श्याम संजीवनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के नाम पर पंजीकरण कराया गया था। इसकी फिटनेस वैधता 31 जनवरी, 2017 को और इंश्योरेंस दस जनवरी 2017 को समाप्त हो चुका है। 23 जनवरी 2020 को संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय से (जिस पते पर एम्बुलेंस का पंजीयन कराया गया था) नोटिस भेजे जाने की बात कही जा रही है। हैरत की बात है कि नोटिस दिए जाने के विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझी।

आगरा शहर की भलाई के लिए मेयर बैठे मौन उपवास पर

आगरा । वायु प्रदूषण के खिलाफ शुक्रवार सुबह 11 बजे से एक माह का जन जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। अभियान का समापन 2 मई को शपथ ग्रहण समारोह से होगा। अभियान के पहले दिन एमजी रोड स्थित स्पीड कलर लैब के सामने मेयर नवीन जैन, राज्य मंत्री जी एस धर्मेश, विधायक महेश गोयल सहित अन्य ने 4 घंटे का मौन व्रत रखा। मेयर ने कहा कि लोगों को ना सिर्फ एक पौधा लगाना चाहिए बल्कि उसकी देखभाल का जिम्मा भी लेना चाहिए।

शुक्रवार को महापौर नवीन जैन मौनव्रत धारण कर 'उम्मीद बदलाव की, शुद्ध आबोहवा की' अभियान को शुरू किया। महापौर नवीन जैन ने बताया कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण से बचाव के लिए चलाया जा रहा है जो 2 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलाया जाएगा।

प्रदूषण के खिलाफ चलने वाले इस जनजागरण अभियान के अंतर्गत विभिन्न चरणों के माध्यम से समस्त आगरावासियों को यह समझाने का प्रयास किया जाएगा कि अपने दैनिक जीवन दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव कर और छोटे-छोटे प्रयासों से वह किस तरह से अपने शहर को प्रदूषण से बचा सकते हैं।

महापौर नवीन जैन ने सभी सामाजिक, स्वयंसेवी, शैक्षिक, व्यापारिक संगठनों व संस्थाओं के साथ शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह समय-समय पर प्रत्येक नागरिक ने आगरा को स्वच्छ, हरित और सुन्दर बनाने के लिए चलाए गये विभिन्न अभियानों व आंदोलनों में सहयोग किया है, उसी तरह एक बार फिर आगरा शहर की आबोहवा शुद्ध बनाने एवं पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए आप सभी पुनः एक बार फिर मेरे इस जनजागरण अभियान का हिस्सा बने। ताकि हम अपने आने वाले कल (भविष्य) को संवार सके और अपने बच्चों या भावी पीढ़ी को वैसा ही शुद्ध वातावरण दे सकें जैसा हम उन्हें देना चाहते हैं।

कार्यक्रम स्थल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के घूमते रहे। वहीं 2 गज की दूरी का पालन नहीं किया गया।

मेरठ में ट्यूशन जा रही नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, आहत छात्रा ने जहर खाकर दे दी जान, दो आरोपित गिरफ्तार

मेरठ । मेरठ में एक बार फिर हैवानियत की वारदात सामने आयी है। सरधना के एक गांव में ट्यूशन जा रही कक्षा दस की छात्र को गांव के ही चार युवकों ने अगवा कर लिया और एक पुरानी हवेली में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। छात्र इतनी आहत हुई कि उसने जहर खा लिया। घर पहुंचने पर स्वजन को घटना का पता चला तो वह उसे लेकर एसडी ग्लोबल अस्पताल पहुंचे जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। छात्र के भाई ने एक नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी थी। अब इसमें दो आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि दो अन्य की तलाश की जा रही है।

पुरानी हवेली में ले जाकर किया दुष्कर्म- कक्षा दस की छात्रा गांव के दूसरे छोर पर रोज शाम चार बजे ट्यूशन पढ़ने जाती थी। छात्र के भाई ने बताया कि गुरुवार को भी किशोरी घर से पौने चार बजे ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी लेकिन शिक्षक के पास नहीं पहुंची। किशोरी के भाई ने आरोप लगाया कि लखन ने रास्ते में अपने तीन साथियों के साथ छात्रा को अगवा कर लिया और खंडहर में बदल चुकी पुरानी हवेली के अंदर ले जाकर चारों ने दुष्कर्म किया। करीब साढ़े पांच बजे छात्रा बदहवास हालत में घर लौटी। उसने स्वजन को दुष्कर्म व जहर खाने की जानकारी दी। स्वजन उसे लेकर एसडी ग्लोबल अस्पताल पहुंचे जहां उपचार के दौरान छात्र की मौत हो गई। इंस्पेक्टर ब्रिजेश सिंह, एसपी देहात केशव कुमार अस्पताल पहुंचे और स्वजन से जानकारी लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

एसपी देहात केशव कुमार ने कहा- छात्र ने जहर खाकर जान दे दी है। किशोरी के भाई ने तहरीर में बताया है कि लखन व उसके तीन साथियों ने दुष्कर्म किया है। मामले की जांच की जा रही है। किशोरी के मोबाइल की काल डिटेल भी निकलवाई जा रही है। वहीं इसमें दो आरोपितों को गिरफ्तार भी किया गया है।

इन दो आरोपितों को किया गया गिरफ्तार- थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विकास पुत्र बलवंत उर्फ बुल्ली व अभय उर्फ लखन पुत्र संजय को गिरफ्तार किया हैं। वहीं रोबिन पुत्र राजू व राजा उर्फ रोकी पुत्र रामा फरार है। पुलिस आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपित पकड़े जाएंगे। फिलहाल, इस मामले मे पुलिस अभी लिखा पढ़ी कर रही है।

लखनऊ में सपा के लिए साख का सवाल बनी सीट नंबर 24

लखनऊ । वैसे तो समाजवादी पार्टी ने जिले की सभी 25 जिला पंचायत सीटों के लिए अपने समर्थित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस बार वार्ड संख्या 24 पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गई है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस सीट को जीतने के लिए पार्टी पदाधिकारियों को विशेष तैयारियां करने के आदेश दिए हैं।

सपा ने जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए सभी 25 वार्डों में समर्थित उम्मीदवार उतारे हैं। सपा ने इस बार जातीय समीकरण भी साधा है। जिला पंचायत सदस्यों की 10 आरक्षित सीटों के अलावा पार्टी ने कुर्मी, मुस्लिम, लोधी को भी अपना समर्थित प्रत्याशी बनाया है। इन सबके बीच बसपा से तीन बार की जिला पंचायत सदस्य पुष्पा रावत को वार्ड संख्या 23 और महेश कुमार वर्मा को वार्ड 24 से अपना उम्मीदवार बनाया है। मोहनलालगंज विधायक अम्ब्रीश सिंह पुष्कर की पत्नी व पूर्व ब्लाक प्रमुख विजय लक्ष्मी इस बार वार्ड 18 से चुनाव मैदान में होंगी। पार्टी के लिए वार्ड संख्या 24 इसलिए भी खास है, क्योंकि पिछली बार विजय बहादुर यादव ने सपा समर्थित के तौर पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था और अब वह भाजपा में है और इसी वार्ड से चुनाव लड़ रहे है।

जिलाध्यक्ष जय सिंह जयंत बताते हैं कि जिला व विधान सभा का संगठन पूरी मजबूती से सभी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। वार्ड 24 को लेकर गोसाईगंज में पार्टी यादव, कुर्मी और आरक्षित जाति के मतदाताओं के बीच पहुंचेगी। पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि किसानों के मुद्दों को लेकर पार्टी वार्ड 23 और 24 के साथ अन्य वार्डों में भी मजबूती से चुनाव लड़ेगी।

ईवीएम मामले पर भारत और राज्य निर्वाचन आयोग अपने स्टैंड पर अड़े, बिहार पंचायत चुनाव लड़नेवालों की बढ़ी धड़कन

पटना । पंचायत चुनाव लडने् के लिए बेताब लाखों लोगों की दुविधा खत्म नहीं होने जा रही है। राज्य सरकार ने कह दिया है कि ईवीएम मशीन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का स्टैंड साफ है। इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग का आदेश अस्वीकार्य है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कहा कि एम थ्री इवीएम से पंचायत चुनाव कराने का राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला सही है। इससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है।

मालूम हो कि ईवीएम विवाद पटना हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। तीन सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय और राज्य चुनाव आयोग को कहा है कि दोनों आपस में बातचीत कर तय कर लें कि किस इवीएम से चुनाव होगा।

इसकी सूचना हाई कोर्ट को दें। छह अप्रैल को हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले चार अप्रैल को दोनों आयोगों के अधिकारी आपस में विचार विमर्श करेंगे। अगर एक राय बन गई तो जल्द ही पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएंगी। ऐसा नहीं हुआ तो मामला अगले कुछ दिनों के लिए और टल जाएगा।

रात होते ही शिक्षिका को लगा देता था फोन, पटना डेयरी कॉलेज का रंगीन मिजाज डीन हुआ बर्खास्त

पटना । बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. रामेश्वर सिंह ने संजय गांधी डेयरी इंजीनियरिंग कॉलेज के डीन डॉ. बलबीर सिंह बेनीवाल को बर्खास्त कर दिया है। उन पर महिला शिक्षिका को रात में फोन करने और अन्य शिक्षकों को परेशान करने का आरोप लगा था। दो वर्ष पहले उनकी नियुक्ति कॉलेज में हुई थी। बताया जा रहा कि नियुक्ति के समय से ही उन पर सवाल उठने लगे थे। उनकी योग्यता पर कई शिक्षकों ने सवाल उठाया था, लेकिन तब विवि प्रशासन ने मामले को दबाए रखा। महिला शिक्षिका के आरोपों और बिहार विधानसभा में मामला उठाए जाने के बाद भी आरोपित डीन कॉलेज में आते रहे। इसके बाद कॉलेज के अन्य शिक्षकों ने हंगामा किया तो डीन को कॉलेज से मना करते हुए जांच शुरू की गई।

विवि की आंतरिक कमेटी ने की डीन के खिलाफ शिकायत की जांच- बिहार विधान परिषद में यह मामला उठा तो विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच कराई गई। इसके बाद डॉ. बेनीवाल को बर्खास्त कर दिया गया। डॉ. बेनीवाल के मामले की जांच के लिए विवि ने आंतरिक कमेटी बनाई थी, जिसने महिलाओं से जुड़े मामले की जांच की। जांच रिपोर्ट आने के बाद विवि प्रशासन ने बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया।

इसके पहले डॉ. बेनीवाल पर हरियाणा में भी छात्राओं ने छेड़खानी करने का आरोप लगाया था और उन्हें निलंबित किया गया था। विवि की कार्यप्रणाली को लेकर एक सप्ताह पहले शिक्षकों ने प्रदर्शन भी किया था। शिक्षकों का कहना है कि विवि प्रशासन शिक्षकों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। कई अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हैं।

राजद के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने इस विश्वविद्यालय के कुलपति पर भी 12 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। यह मामला भी सदन में उठाया जा चुका है। पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने इस मामले में उचित कार्रवाई का आश?वासन दिया था। इस मामले की जांच भी राजभवन कर रहा है।

एडीजी ने शिक्षिका से दुष्कर्म मामले का लिया संज्ञान, स्कूल प्रबंधक को गिरफ्तार करने का निर्देश

गोरखपुर । दुष्कर्म का आरोपित स्कूल प्रबंधक एक माह बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पीड़ित ने एडीजी अखिल कुमार से मुलाकात कर मामले की जानकारी दी। एडीजी ने आरोपित स्कूल प्रबंधक अनिल को गिरफ्तार करने के निर्देश कैंट थानेदार को दिया। न मिलने पर कुर्की व गुंडा एक्ट की प्रक्रिया शुरू करने को कहा।

यह है मामला- एपी पब्लिक स्कूल में तैनात रही शिक्षिका ने 19 फरवरी को प्रबंधक अनिल कुमार सिंह के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी देने और आइटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है। आरोप है कि 2010-2011 के वार्षिक कार्यक्रम के दौरान जिम्मेदारी देकर प्रबंधक ने उसके साथ नशीली दवा पिलाकर दुष्कर्म किया। इस दौरान प्रबंधक ने फोटो और वीडियो बना लिया जिस वजह से वर्ष 2011 से 2019 तक बिना चाहते हुए पास जाना पड़ता था। एक दिसंबर 2020 को शिक्षिका की शादी हो गई। इसके बाद भी अनिल सिंह उसके ऊपर दबाव बनाता रहा। बात न मानने पर आपत्तिजनक फोटो को इंटरनेट मीडिया पर शेयर कर दिया।मुकदमा दर्ज कराने पर 22 फरवरी को पीड़ित के मायके पहुंचकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा।छह मार्च को तत्कालीन एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने स्कूल प्रबंधक पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था, लेकिन वह पकड़ा नहीं गया।

नाबालिग को बहल-फुसलाकर अगवा करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट नम्रता अग्रवाल ने अभियुक्त ब्रजेश उर्फ कार्टून प्रजापति को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दह हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर 17 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

गोला इलाके की 13 वर्षीय किशोरी 26 अप्रैल 2016 को लापता हो गई थी। उसके पिता ने गोला उपनगर के वार्ड संख्या दो निवासी ब्रजेश पर अपहरण का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की तफ्तीश में आरोप सही पाया गया। ब्रजेश को गिरफ्तार कर पुलिस ने किशोरी को उसके चंगुल से मुक्त कराया था। अदालत में अभियोजन का पक्ष रखते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय और नितिन मिश्र ने अभियुक्त को कठोर दंड से दंडित करने की मांग की थी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दंडित करने का फैसला सुनाया।

पति की हत्या करवाने वाली पत्नी व प्रेमी गिरफ्तार- गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र के गगहा नंबर एक गायत्रीपुरम निवासी अजय यादव के हत्या आरोप में पुलिस ने उसकी पत्नी व उसके प्रेमी सुनील निवासी मसहवा लछीपुर गोरखनाथ थाना को गुरुवार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। सुनील ने गड़ासे से गला रेतकर अजय की हत्या की थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त गड़ासा सहित मृतक की बाइक व चप्पल बरामद कर ली है।

घटना का पर्दाफाश करते हुए एएसपी/सीओ कैंपियरगंज राहुल भाटी ने बताया कि अजय बीते 21 मार्च से गायब था। पत्नी ने हत्या की साजिश रचकर थाने पर उसके गुमशुदगी की सूचना दी थी।

अजय का शव मिलने के बाद पुलिस सीडीआर खंगालना शुरू किया तो उसे सुनील साहनी पर संदेह हुआ। पुलिस ने सुनील को भगौती चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। दबाव देते ही सुनील ने पुलिस को बताया कि मृतक की पत्नी कई माह से उसके संपर्क में थी। वह उसके घर में किराये पर रहता था। बाद में वह कमरा छोड़कर हैदराबाद चला गया था।

मृतक की पत्नी के बुलाने वह 15 मार्च को हैदराबाद से लौटा है और फिर से अजय के मकान में किराये पर कमरा लेकर रहने लगा था। उसने मृतक की पत्नी के साथ हत्या की योजना बनाकर उसकी हत्या की है।

एक नजर

कर्नाटक के मंत्री के साथ कथित सेक्स टेप में नजर आ रही महिला के पिता हाई कोर्ट पहुंचे, पुलिस पर किए सवाल

बेंगलुरु । कर्नाटक के पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली से जुड़े सेक्स वीडियो में कथित तौर पर दिखाई देने वाली महिला के पिता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय जाकर पुलिस के उनकी बेटी का बयान दर्ज करने पर सवाल खड़ा किया है। पिता ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी बेटी परिस्थितियों और सियासत की शिकार है और अनेक मीडिया संस्थानों ने उसके वीडियो को गलत तरह से प्रसारित किया। पिता ने कहा कि उन्होंने यह पता लगते ही अपनी बेटी से संपर्क किया कि उसे शिकार बनाया गया है और उस पर अत्यधिक दबाव है। पिता ने कहा कि उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि बेलगावी में अज्ञात प्रभावशाली लोगों ने उनकी बेटी को अगवा कर लिया है। उनकी बेटी ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

याचिका में कहा गया, जांच के दौरान याचिकाकर्ता को पता चला कि उनकी बेटी का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया और सभी कायदों को धता बताया गया। इस बीच पुलिस सूत्रों ने बताया कि महिला का परिवार बेलगावी से विजयपुरा जाकर रहने लगा है और उन्होंने लड़की की सुरक्षा की मांग की है। बेंगलुरु में पुलिस ने कुछ जगहों का मुआयना किया जहां आपत्तिजनक वीडियो शूट होने की बात कही जा रही है।

उदयपुर का नारायण सेवा संस्थान कुंभ मेले में लगाएगा 50 शैयाओं का अस्थायी अस्पताल

उदयपुर । विकलांग लोगों की मदद के लिए कई दशकों से आगे रहा उदयपुर का नारायण सेवा संस्थान हरिद्वार में आयोजित कुम्भ मेले में अस्थायी अस्पताल लगाने जा रहा है। यह अस्पताल पचास बैड क्षमता का होगा। बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के जमावड़े को देखते हुए संस्थान ने अस्थायी अस्पताल लगाए जाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस अस्पताल में चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, ऑपरेशन थिएटर, प्लास्टर रूम, प्रोस्थेसिस और ऑर्थोटिक्स और कैलिपर वर्कशॉप की सुविधाएं दी जाएंगी। इस दौरान नारायण सेवा संस्थान निन्शुल्क माप और कृत्रिम अंग वितरण शिविर का भी आयोजन करेगा। अस्पताल की स्थापना के इस अभियान में सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े नियमों के साथ-साथ स्वच्छता और मास्क पहनने पर प्रमुख ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बताया गया गया कुंभ मेले में आयोजित नारायण सेवा संस्थान के शिविर में संस्थान के स्वयंसेवक लगातार सक्रिय रहेंगे, जो तीर्थयात्रियों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद करेंगे। जिनमें बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की सुविधा प्रदान करना, संतों और तीर्थयात्रियों के लिए फुट मसाज की सुविधा प्रदान करना के अलावा कुंभ मेले में बनाए गए अस्थायी आवास स्थलों की स्वच्छता का ध्यान भी रखना शामिल है। तीर्थयात्रियों को निन्शुल्क मास्क भी वितरित किए जाएंगे।

निन्शुल्क भोजन कराएगा- उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान कुंभ मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों तथा संतों को निन्शुल्क भोजन की सुविधा देने जा रहा है। संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल कहते हैं कि ''हरिद्वार की पवित्र स्थली पर एकत्र होने वाले लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं की मदद का यह अवसर उनके संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर संस्थान लाखों तीर्थयात्रियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों की जरूरतों को भी पूरा करने का प्रयास करेंगा। एनएसएस ने दिव्यांगों और तीर्थयात्रियों के कृत्रिम अंग वितरण शिविर का आयोजन करने का निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि संस्थान 1985 से लगातार सेवा कार्य में जुटा है और यह भविष्य में भी अनवरत जारी रहेगा।

वड़ोदरा में नवजात जुडवां बच्चों को हुआ कोरोना, दोनों अस्पताल में भर्ती

वड़ोदरा । गुजरात के वड़ोदरा में 15 दिन पहले जन्में जुडवां नवजात बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। एसएसजी अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अय्यर ने बताया इन बच्चों को डायरिया और डिहाइड्रेशन के लक्षण के साथ भर्ती कराया गया था। जब इनका कोरोना टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव निकला। फिलहाल दोनों बच्चों की हालत स्थिर बतायी गई है। बता दें कि इन नवजात बच्चों के माता-पिता भी कोरोना संक्रमित पाये गए हैं उनका भी इलाज हो रहा है। गुजरात में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डाली जाये तो यहां 2410 नए मामलों की पुष्टि हुई है और नौ नई संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है। 2015 संक्रमितों को स्वस्थ पाये जाने पर अस्पताल से घर भेज दिया गया है। राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब बढ़कर 3,10,108 तक पहुंच चुकी है। अब तक 2,92,584 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जबकि 12,996 मरीज सक्रिय बताये गए हैं। 4,528 मरीजों की इस महामारी के कारण मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस को 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए रद्द कर दिया है। बुधवार को राज्य में कोरोना संक्रमण के 2360 नए मामले दर्ज किए गए थे और 2004 संक्रमितों को स्वस्थ पाये जाने पर अस्पताल से घर भेजा गया था। नौ संक्रमितों की मौत दर्ज की गई थी।

कोरोना के कहर के बावजूद, बाजारों में जुटी भीड़; कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां

मुंबई । महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। देश में सबसे अधिक सक्रिय मरीजों की संख्या भी इसी राज्य में हैं। इसके बावजूद भी लोग खुले आम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राज्य के कई शहरों से कोरोना नियमों को ताक पर रख घूम रहे लोगों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में भी कोविड नियमों का उल्लंघन करते लोगों की ताजा तस्वीरें सामने आयी हैं।

इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लोग न तो शारीरिक दूरी के नियम का पालन कर रहे हैं और न ही मास्क लगाया हुआ है। इसके साथ ही मुंबई के और भी कई बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में से 61 प्रतिशत मामले अकेले महाराष्ट्र से सामने आये हैं। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 8646 नए मामले सामने आये हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 43183 नए मरीज सामने आये हैं और 249 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। 32,641 मरीजों को स्वस्थ पाये जाने पर अस्पताल से घर भेज दिया गया। राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल 28,56,163 मामले हैं और अब तक 24,33,368 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 3,66,533 सक्रिय मरीज हैं और कुल 54,898 संक्रमितों की जान जा चुकी है। दूसरी ओर देखें तो महाराष्ट्र में हाल के दिनों में कोरोना के बेकाबू होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अकेले मार्च माह में राज्य में 6,51,513 मरीज सामने आये थे। जबकि बीते अक्टूबर से फरवरी के बीच कुल पांच माह में 7,38, 377 मामले सामने आए थे।

तृणमूल ने प्रधानमंत्री की अटकलों को खारिज करते हुए कहा- ममता दूसरी सीट से चुनाव नहीं लड़ रहीं

कोलकाता । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बंगाल में चुनावी रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या वह दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगी क्योंकि नंदीग्राम में उनकी हार तय प्रतीत हो रही है। इसके कुछ घंटे बाद ही बंगाल के सत्तारूढ़ दल ने स्पष्ट किया कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है।

भाजपा नेता जयप्रकाश मजूमदार ने प्रधानमंत्री की बात को दोहराते हुए कहा कि बनर्जी नंदीग्राम में आसन्न हार के बाद दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसे आधारहीन दावों के लिए ''माफी मांगनी चाहिए।'' पार्टी के एक अन्य नेता ने नाम उजागर नहीं करने के अनुरोध के साथ कहा कि ममता के किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं है क्योंकि वह नंदीग्राम सीट पर आसानी से जीत हासिल करेंगी। उल्लेखनीय है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में हिंसा की छिटपुट घटनाओं और मतदान में गड़बड़ी के आरोपों के बावजूद शाम पांच बजे तक 80 फीसद से ज्यादा मतदान हुआ। बूथ पर कब्जा करने और पक्षपातपूर्ण व्यवहार के आरोपों के बीच निर्वाचन आयोग ने बोयल गांव की एक घटना पर रिपोर्ट तलब किया है, जहां भाजपा समर्थकों के कथित घेराव के कारण तृणमूल कांग्रेस प्रमुख करीब दो घंटे तक रुकी रहीं।

पीपीई किट पहने एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जम्मू में जम्मू रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 परीक्षण के लिए एक यात्री से नाक का नमूना एकत्र करता हुआ ।

संयुक्त युद्धाभ्यास में शामिल होंगे ये चार देश, कोच्चि पहुंचे दो फ्रांसीसी जहाज

नई दिल्ली । टोननेर और फ्रिगेट नाम के दो फ्रांसीसी जहाज ला पेरेस संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए कोच्चि पोर्ट पर पहुंच गए है, इन दोनों ही जहाज का स्वागत किया गया. ये जहाज बंगाल की खाड़ी में फ्रांसीसी नौसेना के नेतृत्व में होने वाले ज्वाइंट प्रैक्टिस में भी हिस्सा लेंगें. इनके साथ ही इस प्रैक्टिस में क्वाड के चार देशों की नौसेनाएं भी शामिल होंगे. क्वाड के इन देशों में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान हैं. वहीं मिली जानकारी के अनुसार नौसेनाओं का ये ज्वाइंट प्रैक्टिस 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चलेगा.

यह पहली बार है जब फ्रांसीसी नौसेना क्षेत्रीय जल में क्वाड - भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के सभी चार सदस्यों के साथ एक संयुक्त ड्रिल का आयोजन कर रही है. सूत्रों की माने तो क्वाड देशों की पहली बैठक 12 मार्च को हुई थी, जिसमें दुनियाभर के लिए खतरे के रूप में उभर रहे चीन के लिए परेशानी खड़े करने वाले कई इशारे मिले थे.

वहीं कैडेट अधिकारी शार्लेट ने कहा कि यह अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है. फ्रांसीसी नौसेना में अब कई महिलाओं को शामिल किया गया है. हम कुल फ्रांसीसी नौसेना ताकत का लगभग 15 प्रतिशत हैं.

टोननेर शिप के कैप्टन अरनौद ट्रैंचेंट ने कहा कि इस अभ्यास के दौरान 8 जहाज होंगे, मैं टास्क ग्रुप का कमांडिंग ऑफिसर बनूंगा क्योंकि यह प्रैक्टिस एक फ्रांसीसी पहल है. अलग-अलग नौसेनाओं के इंटरोऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम कई ऐसी ट्रेनिंग करेंगे.

इंडो-पैसिफिक नई नौसेना अधिकारियों की नई पीढ़ी होगी प्रशिक्षित- इसके अलावा दोनों जहाज के स्वागत करने वाले फ्रांसीसी राजदूत इमैनुअल लेनिन ने कहा, ÷हमारी नौसेनाओं ने जो असाधारण स्तर हासिल किया है, उस पर मुझे गर्व है. यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत और इंडो-पैसिफिक नई नौसेना अधिकारियों की नई पीढ़ी के लिए प्रशिक्षण के केंद्र में हैं.'

अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर, निजी कार में ईवीएम मिलने पर भीड़ ने किया था हमला

नई दिल्ली । असम में निजी कार में ईवीएम मिलने के बाद भीड़ के हमले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. ये एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है, जिन्होंने ईवीएम ले जा रही कार पर हमला किया था. सूत्रों के मुताबिक जांच की जा रही है कि तरह से गाड़ी पर हमला किया गया.

ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और वो प्रशासन के संरक्षण में है. गुरुवार को भीड़ ने असम के पथराकंडी विधानसभा में ईवीएम ले जा रही कार पर हमला किया था. भीड़ ने गाड़ी को इस वजह से रोक दिया क्योंकि भीड़ को लगा कि कार चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है. ईसी की कार टूट गई थी, जिसके बाद अधिकारियों ने पास से गुजरती कार में लिफ्ट ली. बाद में कार की पहचान बीजेपी की गाड़ी के रूप में की गई. कार में ईवीएम पाए जाने के मामले में राजनीतिक रूप ले लिया. असम के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, प्रियंका गांधी और बदरुद्दीन अजमल ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और चुनाव आयोग से मामले की जांच की मांग की.

प्रियंका गांधी वाड्रा का आरोप

प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी और केंद्र सरकार को मामले पर घेरते हुए ट्वीट किया. प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि हर बार निजी गाड़ियों में ईवीएम ले जाने के वीडियो सामने आते हैं, उनमें कुछ चीजें कॉमन हैं. निजी गाड़ियां बीजेपी उम्मीदवारों और उनके सहयोगियों की होती हैं. वीडियो को घटना बताकर खारिज कर दिया जाता है. प्रियंका ने लिखा कि बीजेपी अपने मीडिया तंत्र का इस्तेमाल उन लोगों पर आरोप लगाने के लिए करती है, जिन्होंने वीडियो को उजागर किया.

तथ्य यह है कि इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है. चुनाव आयोग को इन शिकायतों पर निर्णायक रूप से कार्रवाई करने और ईवीएम से जुड़े मामलों के पुनर्मूल्यांकन की जरूरत है.

महाराष्ट्र में लग सकता है लॉकडाउन, सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई बैठक; बद से बदतर हुए हालात

मुंबई । महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं, मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यों के अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक करेंगे। राज्?य में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। बता दें कि बीते कई दिनों से राज्?य के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू और आंशिक प्रतिबंध लागू किया जा चुका है लेकिन कोरोना के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं।

महाराष्ट्र में वीरवार को कोरोना संक्रमण के 43183 नए मामले सामने आए हैं और 32,641 मरीजों को ठीक होने पर अस्पताल से घर भेजा गया। 249 संक्रमितों की इस महामारी के कारण जान चली गई। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 28,56,163 मामले सामने आ चुके हैं जिसमें से 3,66,533 मरीज सक्रिय बताये गए हैं। अब तक कुल 24,33,368 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे में मुंबई में 8,646 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 5,031 लोगों को अस्पताल से घर भेजा जा चुका है। वीरवार को मुंबई में इस महामारी के कारण 18 लोगों की मौत दर्ज की गई है।

पुणे में स्थिति विस्फोटक

पूरे देश के कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर नजर डाली जाये तो महाराष्ट्र के पुणे शहर में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित हैं। यहां दिनों दिन स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। प्रदेश में अब तक कुल 62,45,860 लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। बुधवार को राज्य में कुल 2,16,211 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई। अब तक यहां 10,00,918 स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन की पहली खुराक और 4,79,298 स्वास्थ्यकर्मियों वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। इसी तरह 8,78,535 फ्रंट लाइन वर्कर को पहली और 2,64,659 को दूसरी खुराक दी गई है।

कश्मीर में 10 माह में एक दर्जन भाजपा कार्यकर्ता आतंकी हमलों में मारे जा चुके

श्रीनगर । जम्मू कश्मीर में बीते एक साल के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आतंकी हमलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वीरवार को श्रीनगर के नौगाम में भाजपा नेता अनवर खान के मकान पर हमले से तीन दिन पहले सोपोर में भाजपा से संबंधित नगर पालिका के दो पार्षद और एक पुलिसकर्मी भी आतंकी हमले में शहीद हुए हैं।

यह हमले आतंकियों द्वारा कश्मीर में मुख्यधारा की सियासत से जुड़े लोगों पर किए जाने वाले हमलों से पूरी तरह अलग हैं, क्योंकि हमलावर संगठन एक ही है और हर बार वह इन हमलों को कश्मीर में हिंदुत्व के खिलाफ अपने जिहाद के साथ जोड़ते हुए कहता है कि जो भी भगवा पार्टी का साथ देगा या उसके एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए कश्मीर को भारतीय मुख्यधारा में ले जाएगा, उसका यही हश्र होगा। हमला करने वाला संगठन द रजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर पुलिस इसे लश्कर-ए-तैयबा का एक हिट स्क्वाड और छद्म संगठन बताती है।

कश्मीर में बीते 10 माह के दौरान करीब एक दर्जन भाजपा कार्यकर्ता विभिन्न आतंकी हमलों में मारे जा चुके हैं। आठ जुलाई 2020 को बांडीपोरा में आतंकियों ने भाजपा नेता वसीम बारी की उनके पिता बशीर अहमद और भाई उमर सुल्तान संग उनके घर में ही हत्या कर दी। वसीम के पिता और भाई भी भाजपा के कार्यकर्ता थे। इसके लगभग एक माह बाद नौ अगस्त 2020 को ओमपोरा, बडग़ाम में भाजपा नेता अब्दुल हमीद नजार भी आतंकी हमले में मारे गए।

बडगाम में अब्दुल हमीद नजार की हत्या से तीन दिन पहले छह अगस्त को वेस्सु काजीगुंड में भाजपा से संबंधित एक सरपंच सज्जाद अहमद खांडे आतंकी हमले में मारे गए थे। इसके बाद 23 सितंबर 2020 को बडगाम में भाजपा समर्थित ब्लाक विकास परिषद के चेयरमैन सरदार

भूपेंद्र सिंह की आतंकियों ने उनके घर के बाहर हत्या कर दी थी। 29 अक्टूबर 2020 को कुलगाम में भाजपा के तीन कार्यकर्ता फिदा हुसैन यत्तु, उमर रशीद बेग और उमर रमजान हज्जाम की भी आतंकियों ने अगवा कर हत्या कर दी थी।

आतंकियों के लगातार बढ़ते हमलों से वादी में सक्रिय भाजपा नेता व कार्यकर्ता अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं। कई नेताओं को अपने पुश्तैनी घरों में गए कई-कई साल हो चुके हैं।

राष्ट्रीय एकीकरण पर हमला : कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ आसिफ कुरैशी ने कहा कि भाजपा की छवि एक ङ्क्षहदूवादी दल की है, जो उससे जुड़ता है वह कश्मीर में सक्रिय जिहादी संगठनों की आंख की किरकिरी बन जाता है। पांच अगस्त 2019 के बाद तो भाजपा से जुड़े लोगों को आतंकी व अलगाववादी इस्लाम का दुश्मन करार दे रहे हैं। नेशनल कांफ्रेंस के कार्यकताओं पर हुए आतंकी हमलों को अगर कश्मीर में लोकतंत्र पर हमले की संज्ञा दी गई है तो फिर भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले को राष्ट्रीय एकीकरण पर ही हमला कहा जाएगा।

खतरा ज्यादा, पर हौसला कमजोर नहीं हुआ : भाजपा नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि कश्मीर में भाजपा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता सबसे ज्यादा खतरे में हैं। भाजपा का एजेंडा पूरी तरह राष्ट्रवादी है, भाजपा कश्मीर में जितनी मजबूत होगी, अलगाववादी व आतंकी एजेंडा उतना ही कमजोर होगा। हमारे लोग जानते हैं कि वह खतरे में हैं, बावजूद इसके उनका हौसला कमजोर नहीं हुआ है। हमने कई बार प्रशासन को अपनी सुरक्षा के संदर्भ में लिखा है, लेकिन आज तक हमारे लोगों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध नहीं हुआ है। हमारे अधिकांश साथी आज भी भूमिगत रहकर यहां काम कर रह हैं। कश्मीर में हमारे करीब साढ़े पांच लाख सदस्य हैं।

सुरक्षा की नए सिरे से की जा रही समीक्षा : कश्मीर के आइजीपी विजय कुमार ने कहा कि वादी में लगभग 200 भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। सभी की सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमले सरहद पार बैठी भारत की दुश्मन एजेंसियों के इशारे पर हो रहे हैं।

कोरोना के 53 प्रतिशत मामले सिर्फ महाराष्ट्र में, बीते 24 घंटों के आंकड़ों ने तोड़ा 6 महीने का रिकॉर्ड

नई दिल्ली । भारत में गुरुवार को सामने आए कोरोना के मामलों ने पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया. देश भर से बीते 24 घंटों में कोरोना के 81 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं. पिछले 6 महीनों में इतने केस सामने नहीं आए थे, जितने बीते दिन सिर्फ एक दिन में दर्ज किए गए हैं. देश में महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार में तेज उछाल देखा जा रहा है.

गुरुवार को देश भर से कोरोना के 81,456 मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 1,23,03,131 हो गई है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 80 हजार से ज्यादा मामले आखिरी बार 1 अक्टूबर को सामने आए थे, इस दिन कोविड के 84,176 नए मरीज दर्ज हुए थे.

मौत के आंकड़ों पर बात करें तो बीते दिन कोरोना से 469 मरीजों ने दम तोड़ दिया. मृतकों की यह संख्या 117 दिनों में भी सबसे ज्यादा है. पिछली साल 5 दिसंबर को 400 से ज्यादा यानी 482 मरीजों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई थी.

कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में गुरुवार को 43,183 नए मामले सामने आए. इस राज्य से दर्ज नए मामले देश से सामने आए कुल मामलों के लिए 53 प्रतिशत जिम्मेदार है. कोरोना के कुल मामलों की संख्या में 53 फीसदी हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की है.

महाराष्ट्र में कोरोना के 8,646 नए मामले - वहीं मुंबई से कोरोना के 8,646 नए मामले दर्ज किए गए, जो 28 मार्च के बाद से सबसे ज्यादा (6,933) है. महाराष्ट्र में 1 अप्रैल को 249 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जो 5 नवंबर के बाद से सबसे ज्यादा (256) है. राज्य में लगातार दूसरे दिन कोरोना से 200 से अधिक मरीजों की मौतें हुई हैं.

पंजाब में बीते 24 घंटों में 60 की मौत- महाराष्ट्र के अलावा दो अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामलों में उछाल आया है. ये राज्य पंजाब और छत्तीसगढ़ हैं. पंजाब में गुरुवार को कोरोना के 3,187 केस सामने आए. जबकि छत्तीसगढ़ में 4,617 मामले दर्ज हुए. कर्नाटक से कोरोना के 4,234 नए मामलों की सूचना मिली है. महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मौते पंजाब में हुई. पंजाब में बीते 24 घंटों में 60 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो गई.

देश में एक्टिव मामलों की संख्या 6,14,696- देश में 1 अप्रैल को कोरोना के 80 हजार से ज्यादा मामले यानी 81,466 मामले सामने आए हैं. इस दौरान कुल 469 लोगों ने दम तोड़ दिया. देश में कुल मामलों की संख्या 1,23,03,131 हो गई है. बीते 24 घंटों में 50, 356 लोग संक्रमण से मुक्त होकर घर लौट गए. जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर अब 1,15,25,039 हो गई है.

देश में एक्टिव मामलों की संख्या 6,14,696 है. कोरोना से अब तक 1,63,396 लोग दम तोड़ चुके हैं. मालूम हो कि गुरुवार को देश भर में 36,71,242 लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन किया गया. इसी के साथ अब तक 6,87,89,138 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है.

कांग्रेस में 10 माह से संगठन नहीं, फिर भी हो रही फर्जी नियुक्तियां, उप चुनाव अभियान मंत्रियों के हवाले

जयपुर । राजस्थान कांग्रेस में पिछले 10 माह से जिलों से लेकर ब्लॉक स्तर तक संगठन नहीं है। जुलाई, 2020 में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक संगठन की कार्यकारिणी को भंग किया गया था। अग्रिम संगठन और पार्टी के सभी प्रकोष्ठ भी भंग किए गए थे। पार्टी आलाकमान ने संगठन की सभी इकाईयों को भंग कर दिया था। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी तो बन गई, लेकिन अन्य नियुक्तियां नहीं हुई। बिना पदाधिकारियों के ही स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव हो गए।

संगठन कमजोर होने के कारण दोनों ही चुनाव में सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस को अपेक्षा के मुताबिक सफलता नहीं मिल सकी। पार्टी नेतृत्व द्वारा प्रदेश में संगठन की जा रही उपेक्षा का ही परिणाम है कि भंग कार्यकारिणी के पदाधिकारी अब तक नियुक्तियां कर रहे हैं। नियुक्तियां करने वाले पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। यह आरोप पिछले कई सालों से पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। खुद को निष्ठावान बताने वाले कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जो नेता खुद पद पर नहीं है वे नियुक्तियां कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तक शिकायतें पहुंच रही है, लेकिन वे नियुक्तियां करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाने में असहाय साबित हो रहे हैं।

जयपुर सहित कई जिलों में नियुक्तियां हो रही है। पिछले एक माह में खुद को जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी का महासचिव बताने वाले मनोज दुग्गल ने एक दर्जन से अधिक नियुक्तियां कर दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी इन नियुक्तियों को असैंवधानिक बता रहे हैं, लेकिन दुग्गल लगातार नियुक्तियां करते जा रहे हैं। इसी तरह पाली, कोटा, टोंक व सीकर जिलों में नियुक्तियां हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जसवंत गुर्जर का कहना है कि वर्तमान में जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी व अग्रिम संगठन की कार्यकारिणी भंग है ऐसे में नियुक्तियां करना असंवैधानिक है।

पुलवामा में सुरक्षाबलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, भाजाप नेता के घर पर हमले में थे शामिल

श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर में गुरुवार को भाजाप नेता के घर हुए हमले में शहीद हुए एक जवान की शहादत का बदला भारतीय सुरक्षाबलों ने ले लिया है। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षाबलों ने तीन आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। शुक्रवार सुबह से ही यह मुठभेड़ जारी थी। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के काकापोरा इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान तीनों आतंकियों को घेरने में कामयाबी मिली और लंबी चली

मुठभेड़ के बाद इन्हें मार गिराया गया। सुरक्षाबलों पर आतंकियों की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही थी। फिलहाल ऑपरेशन जारी है।

कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि पुलवामा एनकाउंटर में मारे गए ये तीनों आतंकी भाजपा नेता के घर पर हुए हमले में शामिल थे। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि सुबह से ही पुलवामा में सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेर रखा था। पुलिस के मुताबिक, ऑपरेशन के दौरान पुलिस कर्मियों पर गोलियां चला दी गईं, जिसके बाद उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। अधिकारी ने बताया कि सुबह से ही दोनों ओर से गोलीबारी अब भी जारी थी।

दरअसल, गुरुवार को जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर के बाहरी इलाके में स्थानीय भाजपा नेता पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया था। पुलिस ने बताया कि चार में से एक आतंकवादी बुर्का पहनकर आया था और अरिगाम नौगाम स्थित भाजपा नेता अनवर अहमद से मिलने का अनुरोध किया था। अधिकारी ने बताया कि बारामूला जिले के भाजपा महासचिव एवं कुपवाड़ा जिले के प्रभारी अहमद घटना के समय मकान में मौजूद नहीं थे।

क्या हुआ था कल- अधिकारी ने बताया कि जैसे ही संतरी ने दरवाजा खोला आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिससे संतरी की मौत हो गई। संतरी की पहचान रमीज रजा के तौर पर हुई है। रजा को एसएमएचएस अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि अंदर मौजूद अन्य गार्ड द्वारा जवाबी कार्रवाई किए जाने के डर से आतंकवादी भाजपा नेता के घर पर नहीं होने की सूचना मिलने पर भाग गए। हालांकि वे एसएलआर राइफल लूट ले गए।

यह घटना उत्तरी कश्मीर स्थित बारामूला जिले के सोपोर में ब्लॉक विकास परिषद (बीडीसी) के सदस्य एवं उसके सुरक्षा गार्ड की आतंकवादियों द्वारा हत्या करने के तीन दिन बाद हुई है।

श्वेता तिवारी

ने बताया दर्द, कहा- लोग कहते हैं कि मैंने दो शादी की तो पलक पांच शादियां करेगी

कसौटी जिंदगी के फेम श्वेता तिवारी ने एक्टिंग की दुनिया में खूब नाम कमाया है. सीरियल्स में कई बार उन्हें सच्चा प्यार मिला लेकिन रीयल लाइफ में उन्होंने इस मामले में हर धोखा ही खाया है. श्वेता ने कई बार ये बताया है कि राजा चौधरी के साथ शादी करना उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था.राजा उन्हें कई बार मारते-पीटते थे. और उनकी बेटी पलक भी कई बार ये देख चुकी थी. वहीं अब श्वेता ने ट्रोलिंग पर खुलकर बात की है.जिससे कई बार उन्हें और उनकी बेटी पलक को गजरना पड़ता है.

सोशल मीडिया पर लोग बोलते हैं पलक 5 शादियां करेगी

एक इंटरव्यू में श्वेता ने बताया कि कई लोग उन्हें अब तीसरी शादी ना करने की सलाह देते हैं, और उनकी बेटी पलक को कहा जाता है कि, मां ने दो शादियां की तो बेटी तो कम से कम पांट बार शादी करेगी. श्वेता ने आगे कहा कि, कई लोग सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं फिर अचानक एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं.लेकिन फिर भी उनपर कोई सवाल नहीं उठाता. और मैंने अगर गलत शादी से बाहर निकलने का फैसला किया तो सवालों की झड़ी लगा दी. इतना ही नहीं कई लोग तो ऐसे हैं जो मुझे आकर ये बताते हैं कि, तीसरी बार शादी मत करना.तो क्या मैंने उनसे पूछा ? वो हैं कौन जो मुझे ये बताएंगे ? ये मेरी जिंदगी है और इसका फैसला लेना का हक भी सिर्फ मेरा है.

पलक ने बहुत कुछ देखा है वो सोच-समझकर फैसला लेगी

वहीं श्वेता ने सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले लोगों के बारे में बात करते हुए कहा कि, इंस्टाग्राम पर कई लोग मुझे कहते हैं कि जब मैंने दो शादी की है तो मेरी बेटी पलक तो पांच शादियां करेगी. लेकिन सच कहूं मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो कभी भी शादी करेगी.उसने छोटी सी उम्र में अपनी मां को मार खाते हुए देखा है. और ये सब देखकर तो वो शादी का फैसला बहुत सोच समझकर लेगी.

दो बार शादी कर चुकी है श्वेता तिवारी

बता दें कि श्वेता ने पहले राजा चौधरी से शादी की थी. और घरेलू हिंसा का शिकार होने पर उन्होंने 2007 में राजा से तलाक ले लिया. इसके बाद साल 2013 में उन्होंने एक्टर अभिनव कोहली से शादी की लेकिन इस बार भी उनकी किस्मत खराब रही. दोनों का रिश्ता ज्यादा नहीं टिक पाया.और अलग हो गए.

नेहा कक्कड़

ने अपने भाई को दिया खास तोहफा, घर में बनवा दिया खेलने के लिए क्रिकेट पिच

सिंगर नेहा कक्कड़ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नए-नए पोस्ट शेयर करती रहती हैं. एक बार फिर नेहा कक्कड़ ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो अपने भाई टोनी कक्कड़ के लिए एक तोहफा देती दिखाई दे रही हैं. नेहा ने टोनी कक्कड़ के लिए घर में ही क्रिकेट पिच तैयार करवा दी है. नेहा कक्कड़ का ये सरप्राइज देखकर टोनी कक्कड़ हैरान हो गए. आपको बता दें कि टोनी कक्कड़ को क्रिकेट का बहुत शौक है.

नेहा कक्कड़ ने इस फोटो को शेयर करने के साथ कैप्शन में लिखा, 'घर पर ही क्रिकेट पिच ! काम प्रगति पर है. गिफ्ट कैसा लगा ? टोनी कक्कड़ (Tony Kakkar). आपकी छोटी बहन नेहा.' इस पोस्ट पर फैन्स के साथ-साथ कई सेलेब्स भी खूब रिएक्शन दे रहे हैं. इस वीडियो को दो घंटे पहले शेयर किया गया था और इस वीडियो को अभी तक 5 लाथ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. अगर आपको नेहा कक्कड़ की फैन फॉलोइंग के बारे में नहीं पता है तो आपको बता दें सिंगर के सोशल मीडिया पर 53.8 मिलियन फैन फॉलोइंग है. नेहा कक्कड़ बॉलीवुड की ऐसी सिंगर हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग की संख्या करोड़ों में है.

वर्क फ्रंट की बात करें तो नेहा कक्कड़ इन दिनों इंडियन आइडल सीजन 12 में बतौर जज दिखाई दे रही हैं. कुछ दिनों पहले नेहा कक्कड़ का नया गाना सामने आया था जिसका नाम है %मरजानेया% जिसे लोगों ने अपना खूब प्यार दिया. इस गाने में नेहा की सिंगिंग और रुबिना दिलैक और अभिनव शुक्ला की केमिस्ट्री सबको बहुत ज्यादा पसंज आई. नेहा कक्कड़, रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला के इस गाने को सभी सितारों और लोगों का खूब प्यार मिला.

शाहिद कपूर ने पहना तीन लेयर प्रोटेक्शन मास्क, पैपराजी ने पूछा ऐसा सवाल, तो एक्टर ने धांसू जवाब

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर तीन लेयर प्रोटेक्शन वाला मास्क पहने हुए देखा गया था. शाहिद का ये लुक देखकर कई फैंस रिएक्शन दे रहे हैं. वहीं एक पैपराजी ने भी शाहिद से पूछा कि क्या वह तीन लेयर मास्क के अंदर सही से सांस ले पा रहे हैं और उनके इस एयरपोर्ट लुक की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की.

बॉलीवुड पैपराजी विरल भैयानी शाहिद कपूर की तीन लेयर मास्क पहने हुए तस्वीर शेयर करते लिखा,अगर वह अच्छी तरह से सांस लेने में सक्षम है, तो 5 स्टार्स है. इसके साथ उन्होंने थम्ब्ज अप वाला इमोजी भी इसमें शामिल किया. विरल की इस पोस्ट पर कमेंट कर शाहिद ने एक फनी रिएक्शन दिया है.

एक साल से रोक रखी है सांस

शाहिद कपूर ने लिखा,नहीं, दरअसल मैंने एक साल से ज्यादा वक्त से अबतक सांस रोकी हुई है.शाहिद के इस जवाब से फैंस काफी खुश हुए. एक फैन ने इसे शाहिद का एपिक जवाब बताया. एक फैन लिखा,हाहा गुड वन. एक अन्य फैन ने लिखा,एकदम परफेक्ट जवाब. वहीं एक और फैन ने फायर इमोजी के साथ सेवेज लिखा.

मुंबई में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले

शाहिद कपूर मंगलवार को एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे. उन्होंने मास्क, सनग्लास और एक ट्रांसपैरेंट फेस शील्ड पहना हुआ था. मुंबई में बढ़ती कोरोना वायरस महामारी के चलते शाहिद काफी सावधानी बरत रहे हैं. केंद्र का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी के सबसे ज्यादा मामले देश के शीर्ष 10 शहरों में मुंबई टॉप पर है.

शनाया कपूर

की स्टाइलिश ने किया खुलासा, बताया काम करने का एक्सपीरियंस

बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर की बेटी शनाया बहुत जल्द करण जौहर की फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही है. इस बात की जानकारी करण जौहर ने अपने इंस्ट्राग्राम पर दी थी.

उन्होंने बताया था कि, शनाया ने Dharma Cornerstone Agency को साइन किया है.

वहीं अब शनाया के स्टाइलिश मेगन ने उनके साथ किएग ए काम के दिनों को याद करते हुए शनाया के कई राज खोले हैं.

शनाया की स्टाइलिश मेगन ने खोले कई राज

मेगन ने एक इंटरव्यू में बताया कि, रिया कपूर ने हमें 2018 में दिवाली के दिन पहली बार मिलवाया था. तभी से मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया था. उन्होंने बताया कि, शनाया बहुत ही अच्छी इंसना है. उनके साथ काम करना बहुत ही ज्यादा आसान है. वो एक खुशमिजाज लड़की है.और हमेशा अच्छे मूड में ही रहती हैं. इसलिए उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है. उनके साथ मैंने बहुत अच्छा वक्त बिताया है. वो बहुत ही प्रोफेशनल है. हर काम को बिल्कुल टाईम पर करती है.

शनाया बहुत ही चुलबुली इंसना है - मेगन

मेगन ने आगे बताया कि, शनाया बहुत ही चुलबुली और एनर्जी वाली लड़की है.और उनकी यही बात उन्हें दूसरों से एकदम अलग बनाती है. वो खुद भी हमेशा खुश रहती है. और अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को भी खुश रखती है. मैं उनके साथ काम करते हुए कभी बोर नहीं हूं. और मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद है.

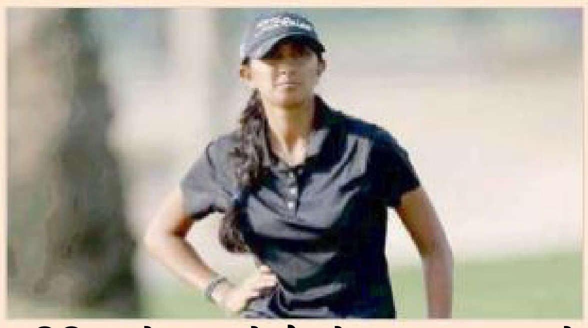

अदिति अशोक पहले दौर के बाद संयुक्त 70वें स्थान पर

रैंचो मिराज (अमेरिका) । भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने इस साल के पहले मेजर एएनए इन्स्परेशन गोल्फ टूर्नामेंट के पहले दौर में एक ओवर 73 का स्कोर बनाया और वह संयुक्त 70वें स्थान पर हैं। अदिति अपने 16वें मेजर में खेल रही हैं। उन्होंने 10वें होल से शुरुआत की और उसी में शॉट गंवा दिया। अगले 10 होल में उन्होंने पार स्कोर बनाया। उन्होंने अपनी एकमात्र बर्डी पार-4 वाले तीसरे होल में बनायी लेकिन पार-3 के पांचवें होल में वह बोगी कर गई। इसके बाद अदिति बाकी होल में पार स्कोर बनाने में सफल रही। अदिति चौथी बार एएनए इन्स्परेशन में खेल रही हैं। वह 2017 में संयुक्त 42वें स्थान पर रही थी जो उनका इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। किसी मेजर में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन संयुक्त 22वां स्थान है जो उन्होंने 2018 में ब्रिटिश ओपन में हासिल किया था। थाईलैंड की पैटी तवातनाकित ने छह अंडर 66 का कार्ड खेला और पहले दौर के बाद बढ़त हासिल की।

उत्तर और दक्षिण कोरिया साथ मिलकर करना चाहते हैं 2032 ओलंपिक की मेजबानी

सियोल.

आपसी संबंधों में कोई मिठास नहीं होने के बावजूद उत्तर और दक्षिण कोरिया ने साथ मिलकर 2032 ओलंपिक की मेजबानी करना चाहते हैं। इस सम्बंध में एक बड़ा बयान उस समय आया जब दक्षिण कोरिया ने कहा कि उसने 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की सह-मेजबानी के लिए उत्तर कोरियाई राजधानी प्योंगयांग के साथ संयुक्त दावा पेश किया है। 2018 के अंत में, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन और उनके उत्तर कोरियाई समकक्ष किम जोंग उन ने एक शिखर सम्मेलन के दौरान एक संयुक्त ओलंपिक बोली की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन जल्द ही देशों के बीच संबंधों में खटास आ गई और यह महसूस किया गया कि संयुक्त बोली नहीं लगेगीं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कथित तौर पर खेलों के इस महाकुंभ की मेजबानी ऑस्ट्रेलियाई शहर ब्रिस्बेन को देने का इच्छुक है लेकिन इसके बावजूद सियोल की मेट्रोपॉलिटन सरकार ने प्योंगयांग के साथ अपनी संयुक्त बोली के बारे में आईओसी को अवगत करा दिया है। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप ने एक बयान के हवाले से कहा, आईओसी ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन को 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए पसंदीदा होस्ट के रूप में 25 फरवरी को घोषित किया था।

दक्षिण कोरियाई सरकार और सियोल शहर ने तुरंत निर्णय पर खेद व्यक्त किया और आईओसी के साथ विचार-विमर्श किया, जिससे साथ मिलकर ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक की सहमेजबानी की दावेदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने यह भी बताया कि सियोल ने गुरुवार को आईओसी को संयुक्त रूप से 2032 ओलंपिक की मेजबानी के लिए प्योंगयांग के साथ संयुक्त बोली प्रस्ताव भेजा था।

संक्षिप्त समाचार

पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने सचिन तेंदलुकर के लिए मांगी दुआ, कहा- जल्दी ठीक हो जाओ मास्टर

स्पोर्ट्स डेस्क। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस हुआ था जिसके बाद आज उन्हें अस्तपाल में भर्ती करवाया गया है। इसके बाद से ही दुनिया भर से उनके फैंस और साथी खिलाड़ी उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम भी शामिल हो गए हैं। अकरम ने कहा, ल्दी ठीक हो जाओ मास्टर। अकरम ने ट्वीट करते हुए लिखा, जब आप 16 साल के थे, तब भी आपने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों का हिम्मत और हौसले के साथ सामना किया। मुझे यकीन है कि आप कोविड-19 को भी छक्के के लिए भेजेंगे। जल्दी ठीक हो जाओ मास्टर। डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ भारत की वर्ल्ड कप 2011 की वर्षगांठ मनाएंगे तो अच्छा होगा। मुझे एक तस्वीर भेजें।' इसके पहले सचिन ने अस्पताल में दाखिल होने की जानकारी देते हुए ट्वीट करते हुए लिखा था, आपकी शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं के लिए आभार। चिकित्सा सलाह के तहत एहतियात के तौर पर मैं अस्पताल में भर्ती हो गया हूं। मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में मैं घर वापस लौट जाऊंगा। सभी अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ ही विश्व कप जीतने के 10 साल की वर्षगांठ पर सचिन ने कहा, हमारे विश्व कप की 10वीं वर्षगांठ पर सभी भारतीयों और मेरे साथियों को बधाई।

पुरानी लय वापस हासिल करना महत्वपूर्ण होगा : रूपिंदर

ब्यूनस आयर्स. भारतीय पुरुष हॉकी टीम के अनुभवी डिफेंडर रूपिंदर पाल सिंह का कहना है कि अर्जेंटीना के खिलाफ पुरानी लय को वापस हासिल करना महत्वपूर्ण होगा। रूपिंदर का 2019 में बेल्जियम दौरे के बाद यह पहला विदेशी दौरा है। वह इस साल फरवरी में भारत के यूरोप दौरे में चोट के कारण नहीं जा सके थे। रूपिंदर ने कहा, ओलंपिक चैंपियन के खिलाफ खेलने के लिए बेहद उत्साहित हूं। प्रतिस्पर्धी हॉकी में खेले हुए लंबा समय हो गया है। मेरा पिछला विदेशी दौरा सितंबर 2019 में बेल्जियम का था। दुर्भाग्य है कि मैं पिछले यूरोप दौरे पर नहीं जा सका। मैंने इसके लिए काफी मेहनत की थी और मैं जर्मनी तथा ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ खेलने के लिए उत्साहित था। लेकिन चोट के कारण मैं वहां नहीं जा सका, जिसका निजी तौर पर मुझे काफी अफसोस है। उन्होंने कहा, पिछले साल मैं अच्छी फॉर्म में था। अर्जेंटीना के खिलाफ पुरानी लय वापस हासिल करना जरूरी होगा। यह महत्वपूर्ण है कि मैं सामान्य हॉकी खेलूं। मुख्य कोच ग्राहम रीड भी हमेशा कहते हैं कि सामान्य तरीके से खेलना चाहिए। रूपिंदर ने कहा, हम बायो-बबल में ढल गए हैं और प्रोटोकॉल को समझते हैं। हम हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के आभारी हैं, जिन्होंने यह दौरा आयोजित कराया। पेरिस में हवाई अड्डे पर हमें कमरे दिए गए। यहां भी हमने सामाजिक दूरी का पालन किया और हमेशा मास्क पहने रहे।

फेडरर के जन्मदिन को अपने नेशनल डे में बदल सकता है स्विट्जरलैंड

ल्यूसाने. महान टेनिस स्टार रोजर फेडरर दुनिया के लिए एक किंवदंती है, लेकिन अपने देश स्विटजरलैंड के लोगों के लिए फेडरर इससे भी कहीं अधिक बढ़कर हैं। टेनिस की शानदार उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए स्विट्जरलैंड 8 अगस्त, 2021 को अपना नया नेशनल डे के रूप में मनाने की तैयारी कर रहा है। इस दिन फेडरर 40 साल को हो जाएंगे और इसके लिए हालांकि स्विस सरकार को अपना नेशनल डे एक सप्ताह आगे ले जाना होगा। स्विस सरकार राष्ट्र किंवदंती और पूर्व विश्व नंबर-1 को ऐसा एक उपहार देकर सम्मानित करने का इच्छुक है, जो दुनिया के किसी भी देश ने अपने खेल नायक को नहीं दिया होगा। यह सब स्विस संसद में शुरू हुआ, जहां कई सांसदों ने अपने अनोखे तरीके से फेडरर को सम्मानित करने के लिए सोशल मीडिया पर एक पहल शुरू की। जल्द ही, इस कदम ने उनके प्रशंसकों की विरासत के बीच गति प्राप्त की और बहुत जल्द ही यह 80 लाख देशवासियों की बात बन गई। यह पहली बार नहीं है जब यूरोपीय देश टेनिस के महान खिलाड़ी पर स्नेह और कृतज्ञता बरसा रहा है। स्विट्जरलैंड ने फेडरर के सम्मान में बीते साल स्विसमिंट से 20 फ्रैंक का चांदी का सिक्का निकाला था। हाल ही में फेडरर ने स्विस टूरिज्म के साथ करार किया है, जिसके तहत अब दुनिया इस खूबसूरत देश को उसके सबसे महान सपूत की नजरों से देखेगी। वर्षो से स्विटजरलैंड का प्रतिनिधित्व कर रहे फेडरर ने स्विस नेशनल टूरिजम बोर्ड के साथ लंबे अवधि का करार किया है। इसका उद्देश्य स्विटजरलैंड के पर्यटन को बढ़ावा देना है। फेडरर और स्विटजरलैंड टूरिजम साथ में मिलकर वैश्विक रूप से देश में पर्यटन को बढ़ावा देने पर काम करेंगे। कोरोना के कारण पूरे विश्व में पर्यटन के क्षेत्र पर इस महामारी का सर्वाधिक असर पड़ा है। स्विटजरलैंड टूरिजम के सीईओ मार्टिन निदेगर ने कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फेडरर सही व्यक्ति हैं। स्विटजरलैंड और उसकी प्रकृति ने स्पष्ट रूप से फेडरर के अभूतपूर्व करियर में योगदान दिया है। फेडरर ने कहा, मैंने हमेशा सोचा कि जब टेनिस कोर्ट में कदम रखूं तो स्विटजरलैंड का प्रतिनिधित्व करूं। जहां भी मेरा नाम जाए, वहां स्विटजरलैंड का झंडा हो। पिछले 22 वर्षो से ऐसा करके गर्व हो रहा है। स्टिजरलैंड टूरिजम के साथ जुड़ना मेरे लिए लॉजिकल स्टेप है।

इंग्लैंड का विकेटकीपर बल्लेबाज बोला- दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने के बाद खेल में हुआ सुधार

नई दिल्ली ।

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज सैम बिलिंग्स का मानना है कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दिल्ली की टीम के प्रतिनिधित्व करने के बाद उनका खेल बेहतर हुआ है और वह आगामी नौ अप्रैल से शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता में दिल्ली कैपिटल्स के साथ अपने दूसरे कार्यकाल के लिए तैयार है। बिलिंग्स 2016 और 2017 में दिल्ली की फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व कर चुके है। दिल्ली कैपिटल्स ने फरवरी में आईपीएल नीलामी में दो करोड़ रुपए की बोली के साथ उन्हें टीम से जोड़ा था। बिलिंग्स ने कहा, '' पिछली बार दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने के बाद मेरे खेल में सुधार हुआ था। उम्मीद है, हम एक समूह के रूप में लय हासिल कर इस वर्ष प्रतियोगिता जीत सकते हैं।' उन्होंने कहा, 'आईपीएल में वापसी करना शानदार है। यह खिलाड़ियों का एक बड़ा समूह है और दिल्ली कैपिटल्स बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रख रहा हैं। मैं यहां आकर बहुत उत्साहित हूं। इस 29 साल के खिलाड़ी ने 187 टी20 मैचों में 3527 रन बनाने के साथ 107 कैच और 17 स्टंपिंग किए है। उन्होंने कहा, 'मुझे आईपीएल पसंद है। यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंटों में से एक है और इसे लेकर जितनी चर्चा होती है वह दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। मैं टूर्नामेंट में खेलने का इंतजार कर रहा हूं।' नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत दिल्ली केपिटल्स की अगुवाई करेंगे और बिलिंग्स ने उनके साथ अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा, 'मुझे याद है जब मैंने पहली बार ऋषभ को खेलते देखा था। हम अभ्यास कर रहे थे और वह क्रिस मौरिस, नाथन कूल्टर-नाइल और दूसरे गेंदबाजों के खिलाफ आसानी से बड़े-बड़े शॉट लगा रहा था। तब मैंने राहुल द्रविड (टीम के तत्कालीन मेंटोर) से पूछा था कि यह खिलाड़ी कौन है?'

मौजूदा चैंपियन एश बार्टी मियामी ओपन के फाइनल में पहुंची

मियामी ।

विश्व की नंबर एक खिलाड़ी एश बार्टी ने सीधे सेटों में जीत दर्ज करके गुरुवार को यहां मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में प्रवेश किया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बार्टी ने उक्रेन की पांचवीं वरीयता प्राप्त इलिना स्वितोलिना को 6-3, 6-3 से हराया। विश्व रैंकिंग में अपना पहला स्थान सुनिश्चित कर चुकी बार्टी खिताबी मुकाबले में बियांका आंद्रेस्कू और मारिया सकारी के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता से भिड़ेगी। इस बीच पुरुष एकल में 20 वर्षीय सेबेस्टियन कोर्डा का अभियान क्वार्टर फाइनल में थम गया। चौथी वरीयता प्राप्त आंद्रेई रूबलेव ने कोर्डा को 7-5, 7-6 (7) से हराया। कोर्डा 2003 में रॉबी गिनेप्री के बाद मियामी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा अमेरिकी खिलाड़ी बने थे। रूबलेव और पोलैंड के हूबर्ट हरकाज शीर्ष स्तर के एटीपी टूर्नामेंट में अपना पहला सेमीफाइनल खेलेंगे। हरकाज ने दूसरी वरीयता प्राप्त स्टेफनोस सिटिसिपास को 2-6, 6-3, 6-4 से पराजित किया।

अर्जेंटीना और जर्मनी के दौरे से काफी कुछ सीखा : नवजोत

बेंगलुरु. भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड खिलाड़ी नवजोत कौर का कहना है कि टीम ने अर्जेंटीना और जर्मनी के दौरे से काफी कुछ सीखा है। कोरोना के कारण एक साल के अंतराल के बाद भारत ने विश्व की नंबर-2 टीम अर्जेंटीना और जर्मनी के खिलाफ मैच खेला था। हालांकि उसे दोनों टीमों के खिलाफ जीत नहीं मिली थी। नवजोत ने कहा, ÷एक साल के बाद अंतरराष्ट्रीय मुकाबले नहीं खेलने के बाद पहली बार मैदान पर उतारना हमारे लिए उत्साहजनक था। हालांकि, अर्जेंटीना के खिलाफ नतीजे हमारे अनुरूप नहीं रहे। हमारा निजी और एक टीम के रूप में प्रदर्शन ठीक रहा और हमने अर्जेंटीना और जर्मनी के दौरे से काफी कुछ सीखा। उन्होंने कहा, हमें पता है कि विश्व की शीर्ष टीमें खेल को लेकर किस तरह की तैयारियां करती है। शीर्ष की तीन टीमें और विश्व की अन्य टीमों के बीच बड़ा अंतर है। हम सभी इस बारे में जागरूक हैं कि हमें कहां सुधार करना है। नवजोत ने कहा, पिछले साल हमने ट्रेनिंग सत्र में जो किया हमने उसे कार्यान्वित किया। अब हमें शिविर में डिफेंस और आक्रमण में कुछ काम करने की जरूरत है। नवजोत टोक्यो ओलंपिक को देखते हुए फिलहाल यहां भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) में भारतीय टीम के साथ ट्रेनिंग कर रही हैं। शिविर सात अप्रैल को खत्म होगा जिसके बाद 10 दिनों का ब्रेक दिया जाएगा। नवजोत ने कहा, पांच साल का समय काफी लंबा होता है। 2016 रियो डी जेनेरो में मैंने सोचा था कि मैं ओलंपिक के लिए तैयार हूं। लेकिन अब मैं यह कह सकती हूं मेरे खेल में शारीरिक, मानसिक और कौशल स्तर पर बदलाव आया है।

खिलाड़ियों की तरह अंपायरों की भी लय होती है, फायदा उठाना चाहूंगा: मेनन

नई दिल्ली ।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की अंपायरों की 'एलीट पैनल' में शामिल होने के बाद पहली श्रृंखला में शानदार अंपायरिंग करने वाले नितिन मेनन ने कहा कि दबाव में उनका प्रदर्शन और सुधर जाता है तथा वह इस बेहतरीन समय (लय) को जारी रखना चाहेंगे। इस 37 साल के अंपायर को पिछले साल जून में कोविड-19 महामारी के दौरान आईसीसी की एलीट पैनल के अंपायरों में शामिल किया गया था लेकिन उन्हें पहली बार मैदान पर उतरने का मौका फरवरी में मिला। महामारी के कारण आईसीसी को द्विपक्षीय श्रृंखला में स्थानीय अंपायरों को नियुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेनन ने भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चार टेस्ट मैच, पांच टी20 मुकाबले और तीन वने मैचों में अंपायर की भूमिका निभाई। श्रृंखला के दौरान सही फैसले के लिए उनकी काफी तारीफ हुई। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से पहले चेन्नई में पृथकवास कर रहे मेनन ने पीटीआई-भाषा से बातचीत पिछले दो महीने की चुनौतीपूर्ण समय को दिलचस्पी के साथ याद किया। उन्होंने कहा, 'पिछले 2 महीने बहुत अच्छे रहे हैं। यह शानदार संतुष्टि देता है जब लोग आपके अच्छे काम को देखते हैं और उसकी सराहना करते हैं। इसमें अंपायरिंग करना चुनौतीपूर्ण था क्योंकि विश्व कप चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिए दोनों टीमें संघर्ष कर रही थी और विदेशों में प्रभावशाली जीत के साथ यहां पहुंची थी। ऐसी पिचों भी काफी चुनौतीपूर्ण थी।' एस वेंकटराघवन और एस रवि के बाद आईसीसी एलीट पैनल में जगह बनाने वाले तीसरे भारतीय बनें मेनन ने कहा, 'यह श्रृंखला दुनिया की दो शीर्ष रैंकिंग वाली टीमों के बीच था। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, मुझे खुशी है कि हमने अंपायरिंग टीम के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया।'

सीमित ओवरों की श्रृंखला में मेनन के फैसले के खिलाफ 40 बार रेफरल (तीसरी अंपायर की मदद मांगी गई) का इस्तेमाल किया गया लेकिन सिर्फ पांच बार उनके फैसले को बदला गया। लगातार बड़े मैचों में अंपायरिग करने वाले मेनन ने कहा कि यह मानसिक मजबूती के बारे में है।

उन्होंने कहा, 'भारत में आयोजित घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंटों के कारण मेरे लिए लगातार मैचों में भाग लेना कोई नयी बात नहीं है। हम रणजी ट्रॉफी (चार दिवसीय प्रथम श्रेणी मुकाबले) में औसतन 8 मैचों में अंपायरिंग करते है। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच यात्रा भी होती है।

मेरा मानना है कि अंपायरिंग मानसिक मजबूती के बारे में है। जब दबाव ज्यादा होगा तो ध्यान भी ज्यादा देना होगा।' लगातार 2 महीने तक अंपायरिंग करने के बाद मेनन को घर में सिर्फ दो दिन बिताने का मौका मिला। आईपीएल के लिए उन्होंने एक और जैव-सुरक्षित (बायो-बबल) माहौल में आना पड़ा।

उन्होंने कहा कि बायो बबल में रहना काफी चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा, 'यह काफी चुनौतीपूर्ण है। जिस दिन मैच नहीं होता है , उस दिन स्थिति और मुश्किल होती है क्योंकि हम होटल से बाहर नहीं जा सकते। बबल में हम परिवार की तरह रहते है और एक दूसरे का ख्याल रखते है।

मोर्गन का बड़ा बयान, 'द हंड्रेड' और दूसरी लीग्स में खेलना चाहते हैं भारतीय क्रिकेटर

कोलकाता। इंग्लैंड के सीमित ओवरों के प्रारूप के कप्तान इयोन मोर्गन ने दावा किया कि कई भारतीय खिलाड़ी उनके देश की महत्वाकांक्षी 'द हंड्रेड (एक पारी में 100 गेंद का क्रिकेट मैच)' और दुनिया की अन्य फ्रेंचाइजी आधारित क्रिकेट लीगों में भाग लेना चाहते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करने वाले मोर्गन ने खेल के संचालकों से अगले 10 वर्षों के लिए एक खाका तैयार करने का आग्रह किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शीर्ष खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की जगह आकर्षक निजी लीग में कैरियर बनाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े। मोर्गन ने बिना किसी का नाम लिए कहा, 'हम यहां 'द हंड्रेड' के बारे में बात कर रहे है, लेकिन मुझे पता है कि ऐसे कई भारतीय क्रिकेटर हैं जो 'द हंड्रेड' और दुनिया भर की अन्य प्रतियोगिताओं में खेलना पसंद करेंगे।' उन्होंने कहा, 'उन्हें यात्रा करना और नई परिस्थितियों और संस्कृतियों का अनुभव लेना पसंद है और उनके आने से ऐसे टूर्नामेंटों का महत्व भी बढ़ेगा।' 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट को पिछले साल शुरू होना था लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण उसे एक साल के लिए टाल दिया गया था। मोर्गन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) उन देशों के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है जिनके खिलाड़ी निजी लीगों को तरजीह दे रहे है। उन्होंने कहा, 'मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि खेल जिस तेजी से बढ़ रहा है उसमें उस तेजी से बदलाव नहीं आ रहा है।' इंग्लैंड के एकदिवसीय और टी20 टीम के कप्तान ने कहा, 'यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इसे सुधारने की आवश्यकता है क्योंकि आप दूसरे देश के खिलाफ खेलते समय अपनी सर्वश्रेष्ठ एकादश मैदान में उतारने में सक्षम नहीं है क्योंकि वे दुनिया भर की बड़ी लीगों में खेल रहे हैं।'

जापान के कोविड प्रभावित क्षेत्रों में रद्द हो सकती है ओलंपिक मशाल रिले

तोक्यो । तोक्यो 2020 की प्रमुख सीको हाशिमोतो ने शुक्रवार को कहा कि जिन क्षेत्रों में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं वहां ओलंपिक मशाल रिले को रद्द किया जा सकता है। हाशिमोतो ने तोक्यो में नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'एक टीम है जिसने (मशाल रिले में) भाग लेने से इन्कार कर दिया है। प्रत्येक क्षेत्र में वायरस की स्थिति लगातार बदल रही है, इसलिए हमें जल्द से जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता है लेकिन साथ ही आखिरी क्षणों में बदलाव के लिये भी हमारा रुख लचीला होना चाहिए।' समिति अप्रैल के आखिर में जापान में दर्शकों की संख्या को अंतिम रूप देगी। हाशिमोतो से जब तीन अप्रैल से शुरू होने वाली कुछ परीक्षण प्रतियोगिताओं को रद्द करने के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा 'जिस माहौल में खिलाड़ी सुरक्षित महसूस करें, उसमें हम प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाने के लिये प्रतिबद्ध हैं। हमें इस पर कड़ी मेहनत करनी होगी।'